TV उत्तरशक्ति NEWS

मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

हर खबर निष्पक्षता के साथ

मुंबई
वर्ष: 8 अंक 309
शनिवार, 30 मई 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, 3 महीने की डेडलाइन में देशभर में लागू हो '112 आपातकालीन हेल्पलाइन

नई दिल्ली, 29 मई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले तीन महीनों के भीतर एक ही आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, 112, को पूरी तरह से चालू करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में, भारत भर में लोग पुलिस के लिए 100, अग्निशमन सेवाओं के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 और 108, राजमार्गों के लिए 1033 और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1091 जैसे विभिन्न आपातकालीन नंबरों का उपयोग करते हैं। लेकिन दुर्घटनाओं या चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान, इससे अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा होती है और समय पर सहायता प्राप्त करने में देरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि इन सभी हेल्पलाइन नंबरों को एक एकीकृत नंबर, 112 में मिला दिया जाए।

सड़क सुरक्षा संगठन सेवलाइफ फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि आघातकालीन देखभाल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि गंभीर दुर्घटनाओं या आघात की स्थिति में, पीड़ित अक्सर सदमे में होते हैं और हर सेकंड महत्वपूर्ण हो जाता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी से किसी व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना कम हो सकती है, और कहा कि आघातकालीन देखभाल के दौरान गति ₹जीवन रक्षक दवा₹ की तरह काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर 112 हेल्पलाइन को पूरी तरह से चालू करने का निर्देश दिया है। इसने सरकारों से नियमित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने को भी कहा है। अदालत ने आगे अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बैठकों के रिकॉर्ड और प्रगति अपडेट आधिकारिक पोर्टलों पर अपलोड करने का निर्देश दिया।

अदालत ने सभी सरकारी और निजी एम्बुलेंस को एआईएस-125 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार अपग्रेड करने का आदेश दिया। अब प्रत्येक एम्बुलेंस में जीपीएस और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम होंगे जो वास्तविक समय में 112 आपातकालीन नेटवर्क से सीधे जुड़े होंगे। इससे प्रतिक्रिया समय में सुधार होने और आपातकालीन टीमों को पीड़ितों तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है। केंद्र को दुर्घटना के मामलों के लिए राष्ट्रव्यापी चिकित्सा बचाव प्रोटोकॉल जारी करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद राज्यों को इसे लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्घटना पीड़ितों की मदद करते समय कई लोगों के मन में व्याप्त भय पर भी चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा कि लोग अक्सर पुलिस पूछताछ, अदालत में पेशी और कानूनी पेचीदगियों के डर से मदद करने में हिचकिचाते हैं।

महाराष्ट्र में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत, शराब विक्रेता गिरफ्तार

पुणे, 29 मई। पुणे और आसपास के इलाकों में 24 घंटे के भीतर 15 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने मेथनॉल मिली जहरीली शराब के पहलू से मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पिंपरी-चिंचवड के फुगेवाडी इलाके और पुणे के हडपसर में वीरवार को इन मौतों के संबंध में सूचनाएं मिलीं। आबकारी विभाग के अनुसार, इन इलाकों में देसी शराब की कथित तौर पर आपूर्ति करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और दापोडी थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पिंपरी-चिंचवड पुलिस ने बताया कि वीरवार को फुगेवाडी इलाके में पांच लोगों की मौत हुई। पुलिस ने शुरू में कहा था कि पांच में से चार मौतें शराब से जुड़ी नहीं हैं, लेकिन अब सभी लोगों की मौत

की जांच शुरू कर दी गई है। हडपसर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि उनके क्षेत्र में तीन लोगों की मौत हुई बाकी अली-अलग इलाकों में कई और मौत के ममले सामने आए जिसमें मरने वालों की कुल संख्या 15 बताई जा रही है। उन्होंने कहा, ''इन लोगों ने पेट दर्द की शिकायत की थी। मौत का सटीक कारण पता लगाया जा रहा है और जहरीली शराब के पहलू की जांच की जा रही है।

राज्य आबकारी आयुक्त अतुल कानडे ने कहा कि फुगेवाडी में हुई मौतों के बाद विभाग ने जांच शुरू कर दी है। कानडे ने कहा, ''हमने योगेश वानखेडे को हिरासत में लिया है, जिसने फुगेवाडी और हडपसर दोनों जगह शराब की आपूर्ति की थी। उसे पिंपरी चिंचवड पुलिस को सौंप दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है।

'यज्ञ रोका तो रावण-कंस जैसा हश्र तय : सीएम योगी

लखनऊ, 29 मई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए पिछली सरकार पर माफिया तत्वों को संरक्षण देने, कल्याणकारी योजनाओं को रोकने और राज्य भर में अराजकता को पनपने देने का आरोप लगाया। मऊ के मधुबन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य के सुरक्षा माहौल में सुधार किया है और यह सुनिश्चित किया है कि जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचें।

योगी ने कहा कि पिछली सरकार माफिया के आगे झुक गई थी। चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई थी। अब मैं कह सकता हूँ कि आज किसी भी माफिया या गुंडे में किसी भी त्योहार के दौरान गड़बड़ी पैदा करने की हिम्मत नहीं है। अगर कोई भी धार्मिक आयोजन में बाधा डालता है, तो त्योहार तो

मनाया जाएगा, लेकिन उसका अंजाम रावण और कंस की तरह ही तय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं, गुंडे उन्हें परेशान करते थे। अपहरण कभी भी हो सकते थे। व्यापारियों को सूर्यास्त से पहले दुकानें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अगर परिवार का कोई सदस्य सूर्यास्त के बाद घर नहीं पहुंचता था, तो परिवार को चिंता सताने लगती थी कि कहीं उनका क्या न हो जाए। योगी ने कहा कि उस दंगे जैसे माहौल में, अराजकता से भरे वातावरण में, यहां के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। राज्य में नौकरियां नहीं थीं। लेकिन जब वे राज्य से बाहर जाते थे, तो उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोग दस कदम पीछे हट जाते थे। योगी ने कहा-पहले गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। आपने 2014 में देश की बागडोर नरेंद्र मोदी को सौंपी। पिछले 12 वर्षों में आपने भारत को बदलते देखा है। मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए केवल चार जातियाँ हैं।

उन्होंने कहा कि एक जाति गरीबों की, एक युवाओं की, एक महिलाओं की और एक किसान की जो हमें भोजन देता है। अगर आपको याद हो, तो इन चारों में सभी शामिल हैं। अगर इन चारों का उत्थान हो जाए, तो देश चलने लगेगा। मोदी जी दिल्ली में योजनाएँ बनाते थे, लेकिन 2014 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन्हें राज्य में लागू नहीं होने दिया। सपा ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। सपा सरकार माफिया के सामने गिड़गिड़ाती थी।

पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और आसमानी बिजली का कहर, 7 लोगों की मौत

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया मुआवजे का ऐलान

कोलकता, 29 मई। पश्चिम बंगाल में मानसून से पहले ही कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोलकाता, हावड़ा और हुगली समेत राज्य के कई हिस्सों में आए भीषण आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने इन हादसों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

शुक्रवार दोपहर कोलकाता और आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली। उमस के बीच अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते दिन में ही रात जैसा अंधेरा पसर गया। अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर करीब 2:45 बजे हवा की

गति 88 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिसने पूरे महानगर को झकझोर कर रख दिया। दमदम में भी 74 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने भारी नुकसान पहुँचाया है।

तूफान की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण कोलकाता के खुदीराम मेट्रो स्टेशन की छत का एक हिस्सा उड़ गया, जिससे बारिश का पानी स्टेशन परिसर के भीतर घुस गया। वहीं, मशहूर साउथ सिटी मॉल के अंदर भी पानी भरने और हवा के दबाव से कांच के पैनल टूटने की खबरें हैं। शहर की प्रमुख सड़कों जैसे पार्क स्ट्रीट, टॉलीगंज और रासबिहारी एवेन्यू पर सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए, जिससे घंटों तक यातायात ठप रहा।

खराब दृश्यता और तेज हवाओं के कारण कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन करीब एक घंटे तक रोकना पड़ा। रेलवे सेवा भी अछूती नहीं रही; बनगांव और बंदेल-कटवा सेक्शन में पटरियों पर पेड़ गिरने से कई ट्रेनें बीच रास्ते में फंसी रहीं। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण बंगाल के 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉ. हबीबुर रहमान बिस्वास ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक दक्षिण बंगाल में तूफान की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। शनिवार को भी कई जिलों में आंधी-तूफान का अनुमान है।

प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी है और आम जनता को भी खराब मौसम के दौरान घरों के अंदर रहने की सलाह दी है।

राहत और बचाव कार्य की निगरानी स्वयं मंत्री अग्निमित्रा पॉल कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जा सके।

लापता की तलाश

सुमन पुल्लूर प्रजापति माताजी
उम्र – 67 वर्ष
दहिसर (पूर्व), मुंबई
दिनॉक 23/05/2026
समय शाम 8 बजे से लापता है।
यदि आपको इनका कोई पता चले तो
कृपया तुरंत संपर्क करें
संपर्क – प्रदीप प्रजापति
मो. 8097426628
आपकी छोटी सी जानकारी किसी अपने को घर वापस ला सकती है।

NEET Paper Leak पर सुप्रीम कोर्ट की NTA को फटकार

नई दिल्ली, 29 मई। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को फटकार लगाते हुए पूछा कि निगरानी तंत्र और निगरानी समितियों के होते हुए भी इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। यूपीएससी से तुलना करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा में ऐसी घटनाएँ कभी नहीं हुईं और वढरउ प्रणाली से सबक लेने की आवश्यकता है। ये टिप्पणियां NEET-UG पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान आईं, जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता NTA और पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की ओर से पेश हुए। अदालत ने एनटीए और डॉ. राधाकृष्णन द्वारा दायर हलफनामों को रिकॉर्ड में लेते हुए केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने डॉ. राधाकृष्णन से समिति की सिफारिशों के बाद हुई निगरानी की सीमा के बारे में प्रश्न किया। यह देखते हुए कि डॉ. राधाकृष्णन निगरानी समिति में नियुक्त होने से पहले उच्च स्तरीय समिति में सेवा दे चुके थे, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा कि कार्यान्वयन की वास्तव में कितनी निगरानी हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि निगरानी के बावजूद ऐसी विफलता हुई है, तो निगरानी प्रक्रिया में ही खामियां प्रतीत होती हैं। पीठ ने कहा कि यदि निगरानी के बावजूद यह विफलता हुई, तो निगरानी में कोई न कोई चूक अवश्य हुई होगी। अदालत ने डॉ. राधाकृष्णन से यह भी पूछा कि समिति ने किन बातों पर विचार नहीं किया था, जिसके कारण पहले सुझाए गए सुरक्षा उपायों के बावजूद कागजात लीक हो गए।

अदालत की चिंताओं का जवाब देते हुए, डॉ. राधाकृष्णन ने बताया कि समिति ने परीक्षा सुरक्षा और प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुल 101 सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। इनमें से 60 अल्पकालिक सिफारिशें थीं, जिन्हें विशेष रूप से 2025-26 की परीक्षा अवधि के दौरान लागू करने के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि अधिकांश सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं, जबकि अन्य वर्तमान में कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। उनके अनुसार, हाल के महीनों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

TIWARI'S SARASWATI CLASSES
Since 1992
Parents' First Choice for 34+ Years
Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director
ADMISSIONS OPEN
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE
NEET | JEE | MHT-CET
10 DAYS FREE DEMO
Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)
✓ 34+ Years of Academic Excellence
✓ Experienced & Dedicated Faculty
✓ Personal Attention
✓ Printed Notes & Regular Tests
✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams
Santacruz Branch: 101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai-400055
Sion Branch: Opp. SIES College (Old), Near Gurukripa Hotel, Sion (West), Mumbai
Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW: 7738007373

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37
* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध

NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra
ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW

SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
• Std. XI & XII (Sci.)
• NEET
• JEE (Main & Advance)
• MHT-CET
• Polytechnic & Engg
• Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)
M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

त्रिभाषा फामूर्ला है भारत की शिक्षा का नया क्षितिज

-ललित गर्ग

भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि भाषाओं, बोलियों, संस्कृतियों और परंपराओं का विराट संगम है। यहां भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति, संवेदना और सामाजिक चेतना का आधार भी है। ऐसे बहुभाषी देश में शिक्षा व्यवस्था को किस भाषा में संचालित किया जाए और बच्चों को कौन-कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं, यह प्रश्न लंबे समय से बहस और राजनीति का विषय रहा है। इसी संदर्भ में ह्लत्रिभाषा फामूर्लाह्व भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में सामने आया। आज नई शिक्षा नीति-2020 और सीबीएसई के ताजा निर्णय ने इसे नए स्वरूप में पुनः प्रासंगिक बना दिया है। नौवीं कक्षा में दो भारतीय भाषाओं को अनिवार्य करने का निर्णय केवल एक शैक्षिक सुधार नहीं, बल्कि भारत की भाषाई आत्मा को मजबूत करने का दूरदर्शी प्रयास है। त्रिभाषा फामूर्ला मूलतः 1964-66 के कोठारी आयोग की देन है। इसका उद्देश्य था कि भारत के छात्र तीन भाषाएं सीखें-पहली मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हिंदी या अन्य भारतीय भाषा तथा तीसरी अंग्रेजी। इस व्यवस्था के पीछे भावना यह थी कि देश के विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संवाद, समझ और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया जाए।

त्रिभाषा फामूर्ला का उद्देश्य ही था कि उत्तर भारत के बच्चे दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखें और दक्षिण भारत के विद्यार्थी हिंदी से परिचित हों। किंतु दुर्भाग्य से यह नीति अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप सफल नहीं हो सकी। इस असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण राजनीतिक विवाद और भाषाई असंतुलन रहा। विशेषकर दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में इसे हिंदी थोपने के प्रयास के रूप में देखा गया। वहां यह भावना बनी कि केंद्र सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा के नाम पर क्षेत्रीय भाषाओं पर वर्चस्व दिलाना चाहती है। दूसरी ओर उत्तर भारत ने भी त्रिभाषा फामूर्ले की आत्मा को गंभीरता से नहीं अपनाया। यहां अधिकांश राज्यों ने तीसरी भाषा के रूप में किसी दक्षिण भारतीय भाषा को अपनाने के बजाय संस्कृत को शामिल कर औपचारिकता पूरी कर ली। परिणाम यह हुआ कि जिस पारस्परिक भाषाई संवाद एवं सौहार्द की कल्पना की गई थी, वह विकसित नहीं हो सका। आज भी स्थिति यह है कि उत्तर भारत के अधिकांश निजी विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी के साथ फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जापानी जैसी विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की जाती है। कई प्रतिष्ठित स्कूलों में हिंदी तक को गौण बना दिया गया है। यह विडंबना ही है कि विदेशी भाषाएं आधुनिकता और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती हैं, जबकि अपनी मातृभाषा या भारतीय भाषाएं ह्लअतिरिक्त बोझह्व बताई जाती हैं। यह मानसिकता भारतीय भाषाओं के प्रति हीनभावना को दर्शाती है। आश्चर्य है कि दो-तीन विदेशी भाषाएं पढ़ना अभिभावकों को अपने बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं लगता, लेकिन अपनी मातृभाषा और भारतीय भाषाएं सीखने के नाम पर वे सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। यह अनुचित है। सरकार को किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहिए।

त्रिभाषा फामूर्ला भारतीय भाषाओं विशेषतः हिंदी को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक है। यह केवल भाषा सीखने की नीति नहीं, बल्कि भारत की भाषाई एकता और सांस्कृतिक सौहार्द को मजबूत करने का माध्यम है। इस व्यवस्था से उत्तर भारत के विद्यार्थी दक्षिण भारतीय भाषाओं से परिचित होंगे और दक्षिण भारत के विद्यार्थी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं को समझ सकेंगे, जिससे भाषाई दूरी और क्षेत्रीय संकीर्णता कम होगी। साथ ही मातृभाषा आधारित शिक्षा बच्चों की समझ, संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति क्षमता को भी विकसित करती है। आज वैश्वीकरण के दौर में विदेशी भाषाओं का ज्ञान उपयोगी अवश्य है, लेकिन अपनी भाषाओं की उपेक्षा किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक आत्मविश्वास को कमजोर करती है। इसलिए त्रिभाषा फामूर्ला भारतीय भाषाओं को सम्मान देने, हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में मजबूत बनाने तथा भारत की बहुभाषी सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक दूरदर्शी और आवश्यक पहल है।

सीबीएसई और केंद्र सरकार का ताजा निर्णय इसी मानसिकता को बदलने का प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चों द्वारा चुनी गई तीन भाषाओं में कम-से-कम दो भारतीय भाषाएं होंगी। यह व्यवस्था किसी भाषा को थोपने की नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं को सम्मान और अवसर देने की नीति है। नई शिक्षा नीति का सबसे सकारात्मक पक्ष इसका लचीलापन है। इसमें किसी राज्य या विद्यार्थी पर कोई विशेष भाषा अनिवार्य नहीं की गई। छात्र अपनी रुचि और क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार भाषा चुन सकते हैं। यह दृष्टिकोण पहले की तुलना में अधिक व्यावहारिक और लोकतांत्रिक है। त्रिभाषा फामूर्ले की सबसे बड़ी उपयोगिता राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय में दिखाई देती है। भाषा मनुष्य को केवल शब्द नहीं देती, बल्कि सोचने का तरीका, संस्कृति का बोध और समाज की संवेदनाएं भी प्रदान करती है। जब उत्तर भारत का छात्र तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ सीखेगा और दक्षिण भारत का छात्र हिंदी या अन्य उत्तर भारतीय भाषाओं को समझेगा, तब दोनों के बीच मानसिक दूरी स्वतः कम होगी। इससे भाषाई वैमनस्य और क्षेत्रीय संकीर्णता कमजोर होगी। भारत की विविधता को समझने और स्वीकारने की दृष्टि विकसित होगी।

इसके अतिरिक्त बहुभाषी शिक्षा बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए भी लाभकारी मानी गई है। यूनेस्को सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें बताती हैं कि बहुभाषी बच्चे अधिक रचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संवेदनशील होते हैं। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा मिलने से बच्चों की अवधारणात्मक समझ मजबूत होती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि विकसित देशों जैसे- जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस ने अपनी शिक्षा और प्रशासन को अपनी भाषाओं में संचालित किया और विज्ञान-तकनीक में अभूतपूर्व प्रगति की। भारत में भी यदि भारतीय भाषाओं को शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान का माध्यम बनाया जाए तो शिक्षा अधिक व्यापक और समावेशी बन सकती है। हालांकि त्रिभाषा फामूर्ले को लागू करने में कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। यदि उत्तर भारत के स्कूलों में तमिल या तेलुगु पढ़ाई जानी है तो उसके लिए योग्य शिक्षकों और पाठ्य सामग्री की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार दक्षिण भारत में हिंदी शिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन चाहिए। दूसरी चुनौती विद्यार्थियों पर अतिरिक्त शैक्षणिक दबाव की है। कई अभिभावकों को आशंका है कि तीन भाषाएं सीखने से बच्चों पर बोझ बढ़ेगा और उनके परीक्षा परिणाम प्रभावित होंगे। लेकिन यह चिंता तब कम हो जाती है जब सरकार स्पष्ट करती है कि तीसरी भाषा का पाठ्यक्रम हल्का होगा, बोर्ड परीक्षा में उसे शामिल नहीं किया जाएगा और उसका मूल्यांकन आंतरिक होगा।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिभाषा फामूर्ले को अधिक लचीले और व्यावहारिक स्वरूप में लागू करने पर बल दिया, ताकि भारत की भाषाई विविधता को सम्मान मिले और विद्यार्थियों में बहुभाषी क्षमता विकसित हो। भारत में करोड़ों लोग रोजगार, व्यवसाय और सामाजिक संपर्क के कारण स्वाभाविक रूप से अनेक भाषाएं सीख लेते हैं। इसलिए भारतीय भाषाओं को बोझ बताना उचित नहीं कहा जा सकता। नई शिक्षा नीति का यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय भाषाओं को पुनः सम्मान देने की दिशा में कदम है। लंबे समय तक अंग्रेजी को आधुनिकता और सफलता का पर्याय मान लिया गया। परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं में ज्ञान-सृजन और उच्च शिक्षा का विकास बाधित हुआ।

यह भी आवश्यक है कि त्रिभाषा फामूर्ले को राजनीतिक विवाद का विषय न बनाया जाए। भाषा किसी पर थोपने की वस्तु नहीं, बल्कि जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए। यह नीति तभी सफल होगी जब इसमें पारस्परिकता, संवेदनशीलता और संतुलन रहेगा। अंततः कहा जा सकता है कि त्रिभाषा फामूर्ला केवल भाषा शिक्षण की नीति नहीं, बल्कि भारतीय बहुलता को एकसूत्र में पिरोने का राष्ट्रीय अभियान है। नई शिक्षा नीति-2020 ने इसे अधिक लचीला, व्यावहारिक और समावेशी बनाकर नई आशा जगाई है। यदि इसे ईमानदारी, दूरदृष्टि और संतुलन के साथ लागू किया जाए तो यह भारत को भाषाई संघर्षों से निकालकर सांस्कृतिक समन्वय, राष्ट्रीय एकता और ज्ञान-समृद्धि की नई दिशा दे सकता है। भारतीय भाषाओं को सम्मान देना दरअसल भारत की आत्मा को सम्मान देना है।

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में मायावती सभी जातियों को जोड़ने में लगी!

अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 2007 वाले 'सर्वजन' (दलित-ब्राह्मण-मुसलमान) फॉमूर्ले को फिर से लागू करने की कोशिश कर रही है। अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए पार्टी 'भाईचारा कमेटियों' के जरिए सभी जातियों को जोड़ने और टिकट वितरण में सोशल इंजीनियरिंग का दांव आजमा रही है।

हालांकि, पार्टी की राह उतनी आसान नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के चुनावों में हार के बाद, पार्टी का जनाधार काफी सिकुड़ गया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 'बहुजन' से 'सर्वजन' की ओर जाने के पुराने प्रयोग से पार्टी का मूल वोट बैंक भ्रमित हुआ, जिसका फायदा अन्य दलों को मिला। अब 2026-2027 में मायावती एक बार फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग फॉमूर्ले को आजमाकर अपनी खोई हुई ताकत हासिल करने का प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के इस 'सर्वजन' और सोशल इंजीनियरिंग फॉमूर्ले की सफलता और चुनौतियों को विस्तार से जानना जरुरी है ।

बकी करीब 20 सालों के बाद एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिये बसपा के पक्ष में दलितों के साथ ब्राह्मणों एवं मुसलमानों के वोटों की गोलबंदी देखी जा रही है। ब्राह्मणों और मुसलमानों के एक बार फिर बसपा की तरफ रुख करने की वजह में जाया जाए, तो ऐसा लगता है कि योगी राज में ब्राह्मणों को लग रहा है कि उनके साथ यह सरकार नाइंसाफी कर रही है। नौकरशाही से लेकर सरकार तक में महत्वपूर्ण पदों से ब्राह्मणों को दूर रखा गया है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में ब्राह्मण नेताओं का प्रवेश अधिक देखा गया है। जनवरी 2026 में अंबेडकर नगर से भाजपा के दिग्गज नेता राधेश्याम पांडे 51-100 ब्राह्मण समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हुए। उन्होंने मायावती से मुलाकात कर पार्टी जॉइन की। दिसंबर 2025 में ब्राह्मण समाज के बड़े नेता जैसे जितेंद्र मिश्रा, दीपक द्विवेदी, नीरज पांडे, विशाल मिश्रा, वैभव दुबे, अनुराग शुक्ला, मोहित शर्मा भाजपा से बसपा में शामिल हुए। यह 2027 चुनाव से पहले भाजपा को झटका था। जनवरी 2026 में एक अन्य बड़े ब्राह्मण नेता ने मायावती से मुलाकात कर बसपा जॉइन की।

सवाल यह है कि क्या 2027 का उत्तर प्रदेश, 2007 वाला उत्तर प्रदेश है? क्या आज भी ब्राह्मण वोट सत्ता की दिशा तय करता है? क्या दलित समाज अब भी बसपा को अपना सबसे स्वाभाविक राजनीतिक घर मानता है? और क्या मायावती के पास वह संगठन, वे चेहरे और वह आक्रामकता बची है, जो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच खुद के लिए जगह बना सके? इसके लिए 2007 को याद करना जरूरी है। बसपा ने 403 में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। पार्टी का वोट शेयर करीब 30। 4 प्रतिशत था। उस चुनाव में बसपा ने लगभग 86 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से बड़ी संख्या जीतकर विधानसभा पहुंची। सतीश चंद्र मिश्रा उस सोशल इंजीनियरिंग मॉडल का चेहरा बने। नारा था – ह्लब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा।

उस समय राजनीतिक हालात अलग थे। भाजपा कमजोर थी। समाजवादी पार्टी यादव-मुस्लिम पार्टी की छवि में सीमित थी। कांग्रेस हाशिए पर थी और मायावती आक्रामक, निर्णायक तथा सत्ता संभालने वाली नेता के रूप में स्थापित थीं। दलित वोट लगभग पूरी तरह उनके साथ था। जाटव वोट बैंक बसपा की रीढ़ था और गैर-जाटव दलितों में भी पार्टी की पकड़ मजबूत थी।लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर गिरकर करीब 12। 9 प्रतिशत पर पहुंच गया। पार्टी केवल बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट जीत सकी। 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटें मिली थीं और उसका वोट शेयर करीब 22 प्रतिशत था। यानी 2017 से 2022 के बीच पार्टी लगभग आधी राजनीतिक ताकत खो बैठी।

सबसे बड़ा झटका संगठनात्मक स्तर पर लगा। बसपा का कैडर, जो कभी बूथ स्तर तक सक्रिय माना जाता था, धीरे-धीरे निष्क्रिय होता गया। पार्टी के बड़े चेहरे या तो भाजपा और सपा में चले गए या फिर राजनीति से किनारा कर लिया। कई जिलों में बसपा के पास ऐसा स्थानीय नेतृत्व नहीं बचा, जो लड़ाई को जमीन पर मजबूती से खड़ा कर सके।

ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती फिर ब्राह्मण कार्ड क्यों खेल रही हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक जमीन की तलाश। आज यूपी की राजनीति दो बड़े खेमों – भाजपा और सपा – में बंटी हुई है। कांग्रेस का दायरा सीमित है और बसपा लगातार सिकुड़ रही है। मायावती को लगता है कि अगर उन्हें वापसी करनी है, तो कोई बड़ा सामाजिक समीकरण खड़ा करना होगा। सिर्फ दलित वोट के भरोसे सत्ता तक पहुंचना अब संभव नहीं दिखता। यहीं से फिर ब्राह्मण-दलित फॉमूर्ले की चर्चा शुरू होती है।

लेकिन क्या ब्राह्मण समाज आज बसपा के साथ आने की स्थिति में है? 2007 में ब्राह्मणों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर बसपा की तरफ आया था, क्योंकि उन्हें कानून-व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए था। उस दौर में भाजपा सत्ता की मुख्य दावेदार नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक पर जबरदस्त पकड़ बना ली। 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव। हर चुनाव में ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ खड़ा दिखाई दिया। उरऊ और अन्य पोस्ट-पोल सर्वे बताते हैं कि 2022 में भी लगभग 80 प्रतिशत ब्राह्मण वोट भाजपा गठबंधन को मिला। जबकि बसपा ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे और ह्लप्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनह्व भी किए, लेकिन उसे जमीन पर समर्थन नहीं मिला। आज ब्राह्मण वोटर किन आधारों पर वोट करता है? पहला, सत्ता के करीब कौन है। दूसरा, हिंदुत्व की राजनीति में कौन मजबूत है। तीसरा, स्थिर सरकार कौन दे सकता है। इन तीनों पैमानों पर फिलहाल भाजपा मजबूत दिखाई देती है।तो क्या मायावती सिर्फ सांकेतिक राजनीति कर रही हैं या उनके पास कोई गहरी रणनीति है?मायावती अच्छी तरह समझती हैं कि अगर बसपा को राजनीतिक रूप से जिंदा रखना है, तो उसे सिर्फ ह्लदलित पार्टीह्व की छवि से बाहर आना होगा। यही वजह है कि वे ह्लसर्वजनह्व लाइन की तरफ लौटती दिखाई दे रही हैं। ब्राह्मण सम्मेलन उसी रणनीति का हिस्सा हैं।

दूसरी चुनौती दलित वोट बैंक की है। बसपा की सबसे बड़ी ताकत दलित वोट था, खासकर जाटव समुदाय। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में भाजपा ने गैर-जाटव दलितों में बड़ी सेंध लगाई है। पासी, वाल्मीकि, कोरी, धोबी जैसे कई समुदाय भाजपा की तरफ गए। वजह सिर्फ हिंदुत्व नहीं थी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं – मुफ्त राशन, उज्ज्वला, आवास और शौचालय जैसी योजनाओं – का भी बड़ा असर रहा। यानी भाजपा ने सिर्फ सवर्ण राजनीति नहीं की, बल्कि सामाजिक विस्तार भी किया। और यही मायावती की सबसे बड़ी मुश्किल है।

अगर दलित वोट बैंक बिखर रहा हो और ब्राह्मण वोट पहले से भाजपा के साथ हो, तो नया सोशल इंजीनियरिंग मॉडल खड़ा कैसे होगा?2007 में मायावती के पास सत्ता की संभावना थी। लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे। लेकिन आज 2027 की चर्चा में क्या बसपा सत्ता की मुख्य दावेदार दिखती है? शायद नहीं। राजनीति में वोटर सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि जीतने की संभावना भी तलाशता है, खासकर सवर्ण वोटर। यही कारण है कि ब्राह्मण समाज का बड़ा हिस्सा उस पार्टी के साथ जाता है, जो सत्ता में हो या सत्ता के करीब हो।

दूसरी तरफ, अखिलेश यादव ने 2024 में ढऊअ यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की नई राजनीति शुरू की है। समाजवादी पार्टी अब सिर्फ यादव-मुस्लिम पार्टी की छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को इसका फायदा भी मिला। कई दलित इलाकों में सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया। यानी मायावती सिर्फ भाजपा से नहीं, बल्कि सपा से भी लड़ रही हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या बसपा के पास कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा है? सतीश चंद्र मिश्रा अभी भी पार्टी में हैं, लेकिन 2007 वाली ऊर्जा और प्रभाव अब दिखाई नहीं देता। नई पीढ़ी के ब्राह्मण नेताओं में बसपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखता, जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित कर सके। इसके उलट भाजपा के पास ब्राह्मण नेतृत्व की लंबी सूची है।

योगी सरकार में ब्राह्मण मंत्रियों की मौजूदगी हो, संगठन में उनकी भूमिका हो या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व। भाजपा लगातार यह संदेश देती रही है कि ब्राह्मण उसके साथ सुरक्षित हैं। हालांकि समय-समय पर यूपी में ब्राह्मण नाराजगी की चर्चा भी होती रही है। एनकाउंटर राजनीति, ठाकुर वर्चस्व के आरोप और कुछ चर्चित घटनाओं के बाद यह धारणा बनी कि ब्राह्मण समाज का एक वर्ग असहज है। मायावती उसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही हैं।

कुछ जानकारों का कहना है कि मायावती के लिए 2027 में अन्य दलों के साथ गठबंधन करना ज्यादा जरूरी है क्योकि मौजूदा समय में मायावती की पार्टी के प्रदेश में केवल एक विधायक हैं। बसपा लोकसभा, राज्यसभा, यूपी विधान परिषद में शून्य पर है। 2014 के लोकसभा में बसपा का खाता नहीं खुला। 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसके चलते उनके 10 सांसद जीते। 2024 में फिर अकेले लड़ी तो एक बार फिर से पार्टी का रिजल्ट शून्य ही रहा। इसी यूपी में विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2012 में जब मायावती सत्ता से बाहर गईं तो उनके 80 विधायक जीते थे। 2017 के चुनाव में जब भाजपा 325 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता पर काबिज हुई तब बसपा के केवल 19 विधायक जीते। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा यूपी में केवल एक विधायकों तक सिमट गई।

जब दर्पण ही धुंधला हो जाए, तो समाज अपना चेहरा कैसे देखेगा?

-सुरेश गांधी

आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर यह प्रश्न पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली पत्रकारिता आज स्वयं विश्वास के संकट से जूझ रही है। कभी यह पेशा जनजागरण, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम था, लेकिन बदलते दौर में इसके स्वरूप, सरोकार और चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मिशन की पत्रकारिता अब धीरे-धीरे बाजार और मुनाफे की चकाचौंध में सिमटती दिखाई दे रही है। भारतीय पत्रकारिता का इतिहास संघर्ष, साहस और जनसेवा की मिसाल रहा है। जब अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों की आवाज दबाने में लगी थी, तब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ह्लउदन्त मार्तण्डह्व के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। राजा राममोहन राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, अज्ञेय, राजेंद्र माथुर जैसे पत्रकारों ने अपनी कलम को समाज परिवर्तन का हथियार बनाया। उस दौर में पत्रकारिता सत्ता की दलाली नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछने का साहस थी। अखबार हाथ से लिखे जाते थे, संसाधन सीमित थे, लेकिन शब्दों में इतनी ताकत थी कि साम्राज्यवादी शासन की नींद उड़ जाती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आधुनिक तकनीक, रंगीन प्रिंटिंग, डिजिटल मीडिया, चौबीस घंटे चलने वाले समाचार चैनल और सोशल मीडिया की बाढ़ ने पत्रकारिता को बेहद तेज और प्रभावशाली बना दिया है। लेकिन इसी रफ्तार में उसकी आत्मा कहीं खोती हुई नजर आती है। खबर अब जनहित से ज्यादा टीआरपी और क्लिक की वस्तु बन चुकी है। विज्ञापन खबर का रूप ले रहे हैं और विचार भी बिकाऊ हो चुके हैं। जनता तक वही समाचार पहुंचाए जा रहे हैं, जिनसे संस्थानों का आर्थिक हित जुड़ा हो।

सबसे बड़ा संकट पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर आया है। समाज में पत्रकार का सम्मान धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इसका कारण केवल बाहरी दबाव नहीं, बल्कि पत्रकारिता के भीतर पैदा हुई विकृतियां भी हैं। कुछ लोग अवैध कारोबार और व्यक्तिगत स्वार्थों की सुरक्षा के लिए पत्रकारिता का चोला ओढ़ लेते हैं। कई तथाकथित पत्रकारों ने इस पेशे को ब्लैकमेलिंग और दलाली का माध्यम बना दिया है। दुर्भाग्य यह है कि ऐसे लोगों को कई बार संस्थानों का संरक्षण भी मिल जाता है, क्योंकि वे सत्ता और पैसे के समीकरण साधने में माहिर होते हैं। आज पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या वह अब भी समाज और लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? लोकतंत्र के अन्य स्तंभ यदि भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और सत्ता के दबाव से प्रभावित हैं, तो पत्रकारिता की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन दुखद यह है कि अब समाचारों की सत्यता पर भी संदेह होने लगा है। राजनीतिक दलों और बड़े कारोबारी घरानों से गठजोड़ ने कई मीडिया संस्थानों की निष्पक्षता को प्रभावित किया है। जब मालिकान ही राजनीतिक सौदों का हिस्सा बनने लगें, तब नीचे तक व्यवस्था का दूषित होना स्वाभाविक है।

कभी पत्रकारिता सत्ता के सामने सच की मशाल लेकर खड़ी होती थी। कलम की एक चोट साम्राज्य की नींद उड़ा देती थी और अखबार जनता की आवाज हुआ करते थे। लेकिन आज वही पत्रकारिता बाजार, टीआरपी और राजनीतिक गठजोड़ के भंवर में फंसती दिखाई दे रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया अब खुद विश्वास के संकट से गुजर रहा है। खबरें अब जनसरोकार से ज्यादा मुनाफे के तराजू पर तौली जाने लगी हैं। विज्ञापन खबर बन रहे हैं और बहसें प्रायोजित एजेंडों में बदलती जा रही हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि समाज में पत्रकारों के प्रति सम्मान भी लगातार घट रहा है। इसकी वजह सिर्फ बाहरी दबाव नहीं, बल्कि पत्रकारिता के भीतर घुस आई दलाली, ब्लैकमेलिंग और स्वार्थ की संस्कृति भी है। कुछ लोगों ने कलम को जनसेवा नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच और कमाई का हथियार बना लिया है। ऐसे दौर में यह सवाल बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या पत्रकारिता अब भी लोकतंत्र की प्रहरी है या फिर सत्ता और बाजार के बीच समझौतों का माध्यम बनती जा रही है। हिंदी पत्रकारिता दिवस आत्ममंथन का भी अवसर है

पत्रकारिता का यह पतन केवल संस्थागत नहीं, नैतिक भी है। कभी पत्रकारिता को समाज सेवा और जनचेतना का माध्यम माना जाता था। आज यह एक बड़ा उद्योग बन चुका है। इसमें प्रोफेशनलिज्म आना गलत नहीं, लेकिन हर प्रोफेशन का एक नैतिक आधार भी होता है। पत्रकारिता की आत्मा सत्य, निष्पक्षता और जनपक्षधरता में बसती है। यदि यह समाप्त हो जाए, तो पत्रकारिता केवल सूचना बेचने का कारोबार बनकर रह जाएगी। इसके बावजूद पूरी तस्वीर निराशाजनक नहीं है। आज भी हजारों ऐसे पत्रकार हैं जो सीमित संसाधनों और जोखिमों के बीच सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। गांव-कस्बों के स्ट्रिंगर, सीमावर्ती क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाता, बाढ़, दंगे, महामारी और नक्सल प्रभावित इलाकों में जान जोखिम में डालकर खबरें जुटाने वाले पत्रकार–ये आज भी पत्रकारिता के असली चेहरे हैं। कम वेतन या बिना वेतन के बावजूद वे इसलिए टिके हैं क्योंकि उनके भीतर मिशन की भावना अभी जीवित है।

पत्रकारिता कभी आसान पेशा नहीं रही। यह सचमुच ह्लतलवार की धार पर दौड़नेह्व जैसा कार्य है। भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले पत्रकारों को आज भी धमकियां मिलती हैं। कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती है। दुनिया भर में हर वर्ष दर्जनों पत्रकार सच दिखाने की कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में पत्रकारिता केवल नौकरी नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और साहस का नाम है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पत्रकारिता अपने मूल स्वभाव की ओर लौटे। मीडिया संस्थानों को यह समझना होगा कि विश्वसनीयता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। पत्रकारों को भी आत्ममंथन करना होगा कि वे सत्ता और स्वार्थ के साथ खड़े हैं या समाज और सच के साथ। पीत पत्रकारिता, फर्जी खबरों और दलाली की संस्कृति से दूरी बनाकर ही इस पेशे की गरिमा बचाई जा सकती है। हिंदी पत्रकारिता दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण का भी दिन है। यह संकल्प लेने का समय है कि पत्रकारिता को फिर से जनविश्वास का माध्यम बनाया जाए। कलम बिके नहीं, झुके नहीं और समाज के प्रति अपनी जवाबदेही को कभी न भूले। क्योंकि यदि चौथा स्तंभ कमजोर होगा, तो लोकतंत्र की पूरी इमारत हिलने लगेगी। आज जरूरत सिर्फ खबर लिखने की नहीं, बल्कि सच के पक्ष में खड़े होने की है। पत्रकारिता का भविष्य तकनीक से नहीं, उसकी नैतिकता से तय होगा। मिशन की वही लौ यदि फिर प्रज्ज्वलित हुई, तो लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ दोबारा अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा दिखाई देगा।

जब कलम दलाली की गिरफ़्त में हो

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि समाज में पत्रकारों के प्रति सम्मान लगातार घट रहा है। इसका कारण केवल बाहरी दबाव नहीं, बल्कि पत्रकारिता के भीतर पैदा हुई विकृतियां भी हैं। कुछ लोगों ने पत्रकारिता को कमाई का जरिया बना लिया है। ऐसे लोग कलम को समाज सेवा नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ, दबाव और सौदेबाजी का हथियार बना चुके हैं। अवैध कारोबार करने वाले कई लोग पत्रकारिता का चोला ओढ़कर उसे सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि आज ह्लपत्रकारह्व शब्द की गरिमा पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कई तथाकथित पत्रकार अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटते। पैसे और स्वार्थ के लिए साथी पत्रकारों की बलि चढ़ाने तक की घटनाएं सामने आती हैं। प्रशासन और पुलिस से सांठगांठ कर सच उजागर करने वाले पत्रकारों को ही निशाना बनाया जाता है। कुछ मामलों में तो पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग और दलाली का ऐसा नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जिसने पूरे पेशे की साख को चोट पहुंचाई है।

विडंबना यह भी है कि इस गंदगी को रोकने के बजाय कई मीडिया संस्थान ऐसे तत्वों को संरक्षण देते दिखाई देते हैं। कारण साफ है–वे संस्थान के आर्थिक और राजनीतिक हित साधने में उपयोगी साबित होते हैं। जब गंगोत्री ही मैली हो जाए, तो गंगा के स्वच्छ रहने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर आज सबसे बड़ा संकट भीतर से ही खड़ा हुआ है। पत्रकारों के हितों की रक्षा का दावा करने वाले कई संगठन भी अब सवालों के घेरे में हैं। मंचों से बड़ी-बड़ी बातें करने वाले ये संगठन अक्सर वास्तविक संघर्ष के समय गायब नजर आते हैं। पत्रकारों की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, उत्पीड़न या संस्थागत शोषण जैसे मुद्दों पर उनकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। कई संगठन केवल सदस्यता, चंदाखोरी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं तक सीमित होकर रह गए हैं।

पत्रकारिता की असली आत्मा

हालांकि इस अंधेरे के बीच उम्मीद की रोशनी भी मौजूद है। आज भी हजारों पत्रकार ऐसे हैं जो सीमित संसाधनों में, जान जोखिम में डालकर सच सामने ला रहे हैं। गांवों, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों, नक्सल प्रभावित इलाकों और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले पत्रकार आज भी पत्रकारिता की असली आत्मा को जिंदा रखे हुए हैं। उनका सबसे बड़ा मानदेय वेतन नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े होने का आत्मसंतोष है। पत्रकारिता कोई साधारण पेशा नहीं है। यह लोकतंत्र की सांस है। जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और राजनीति पर सवाल उठते हैं, तब समाज की निगाहें मीडिया की ओर जाती हैं। लेकिन यदि मीडिया ही अविश्वसनीय हो जाए, तो लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होने लगती है। इसलिए पत्रकारिता के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती अपनी विश्वसनीयता को बचाने की है। जरूरत इस बात की है कि पत्रकारिता फिर से अपने मूल स्वभाव की ओर लौटे। पीत पत्रकारिता, ब्लैकमेलिंग और दलाली की संस्कृति से दूरी बनाकर ही चौथे स्तंभ की साख बचाई जा सकती है। क्योंकि जिस दिन जनता का भरोसा पूरी तरह टूट गया, उस दिन पत्रकारिता केवल व्यवसाय रह जाएगी–लोकतंत्र का प्रहरी नहीं।

गजलों की दुनिया के आफताब डॉ.बशीर बद्र

-विवेक रंजन श्रीवास्तव-विभूति फीचर्स

उर्दू अदब के इतिहास में,शायरी की दुनिया को अपनी सादगी से रोशन करने वाले अजीम शायर, पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र ने 91 वर्ष की आयु में भोपाल में अपनी अंतिम सांस ली। बशीर साहब का जाना एक जिस्म का रुखसत होना नहीं , बल्कि उर्दू गजल के उस सुनहरे दौर का अवसान है जिसने शायरी को महलों और दरबारों से निकालकर आम आदमी की दहलीज पर ला खड़ा किया था। अयोध्या की सरजमीं पर जन्मे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर प्रोफेसर बने बशीर बद्र ने ताउम्र शब्दों की साधना की। उन्होंने भारी-भरकम और जटिल उर्दू अल्फाज के बजाय आम बोलचाल की जुबान को अपनी गजलों का जेवर बनाया। यही वजह है कि उनकी शायरी सीधे रूह में उतर जाती है। बशीर बद्र साहब की विदाई के इस गमगीन मौके पर उनकी ही लिखी पंक्तियां आज हमारी भावनाओं को जबान दे रही हैं। ज़िंदगी के फलसफे और इसके आखिरी पड़ाव को उन्होंने बरसों पहले जिस खूबसूरती से पिरोया था, वह आज पूरी तरह मौजूं बैठता है।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।

आज वाकई बशीर साहब की ज़िंदगी की शाम हो गई है, लेकिन वे जाते-जाते हमारे पास अपनी यादों और गजलों के ऐसे चिराग छोड़ गए हैं, जिनकी रोशनी कभी मद्धम नहीं पड़ेगी। उनके सफर का थमना हमें उनकी उस बेहद मशहूर गजल की याद दिलाता है ,जिसे फिल्म मसान में भी बेहद शिद्दत के साथ इस्तेमाल किया गया था।

मुसाफि र हैं हम भी, मुसाफि र हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।

बशीर बद्र जी मानवीय संवेदनाओं और मोहब्बत के अमर हस्ताक्षर थे । उनकी शायरी की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे हर दिल के जज्बात को बखूबी शब्द देना जानते थे। समाज का दर्द हो, मोहब्बत की कशिश हो या फिर इंसानी रिश्तों की मजबूरियां, उन्होंने हर रंग को अपनी कलम से मुकम्मल किया। आइए, अदब के इस उस्ताद के कुछ और चुनिंदा और बेहद मकबूल शेरों के जरिए उनके फन को याद करें।

रिश्तों की नाजुकता और जुदाई पर..

कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से,
ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो।

सियासत और समाज के दर्द पर...
लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।

मोहब्बत के हसीन और मुकम्मल अहसास पर..
कोई मिल तो जाएगा मगर तुम्हारी तरह कौन चाहेगा,
चलो मय-कदे में वहीं बात होगी।

रिश्तों के टूटने और बिखरने के सलीके पर...
दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे,
जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों।

बशीर बद्र साहब ने अपने जीवन के आखिरी तीन दशक भोपाल की आबो-हवा में गुजारे। भोपाल की इस ऐतिहासिक और साहित्यिक सरजमीं की यह तासीर रही है कि इसने हमेशा बड़े फनकारों को अपनी गोद में पनाह दी है और निखारा है।

जब हम बशीर बद्र के अवदान को देखते हैं, तो स्वतः ही भोपाल के उन समकक्ष और समकालीन दिग्गजों की याद हो आती है जिन्होंने अपने-अपने दौर में शब्दों की हुकूमत चलाई।

31 मई को सेवानिवृत होने वाले भिवंडी महानगरपालिका के 32 कर्मचारियों का किया गया भव्य सपरिवार सम्मान

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी मनपा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 31 मई को हो रही है और 31मई को रविवार छुट्टी का दिन है जिसके लिए आज मनपा द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सपत्नीक सत्कार का आयोजन किया। बतादें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका के 32 कर्मचारी नियत आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जिनका पालिका मुख्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में सहायक आयुक्त शैलेश देंदे के हाथों सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनकी पत्नियों का शाल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग प्रमुख मिलिंद पलसुले, जनसंपर्क अधिकारी श्रीकांत परदेशी तथा विभिन्न कामगार संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों में सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक हेमंत गुलवी, लिपिक सुरेश जाधव, प्रकाश वेखंडे, रुबीना सिद्धीबापा, वाहन चालक गौतम शेलार, देवचंद सुपे, कुंडलिक मेमाणे सहित अन्य कर्मचारियों का समावेश है। विशेष बात यह है कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि की राशि 1 जून को सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।

मीरा भायंदर में मराठी परिवार को घर देने से इनकार पर मंत्री प्रताप सरनाईक का कड़ा रुख

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। भायंदर वेस्ट में एक मराठी परिवार के साथ कथित भेदभाव का मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री सरनाईक ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि मीरा भायंदर शहर में मराठी लोगों का अपमान या उन्हें आवास देने से इनकार किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला उस समय चर्चा में आया जब भायंदर की रहने वाली श्रीमती रवीना शिंदे को कथित रूप से ह्लमराठी होनेह्व के कारण घर देने से इनकार कर दिया गया। रवीना शिंदे अपने परिवार का पालन-पोषण ह्लशिंदे गुलच चाय और नाश्ता केंद्रह्व चलाकर करती हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री प्रताप सरनाईक स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने रवीना शिंदे के स्टॉल पर जाकर उनके हाथों से चाय पी, पूरे मामले की जानकारी ली और परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद संबंधित मकान मालिक को मौके पर बुलाकर मंत्री ने कड़ी फटकार लगाई और कानूनी परिणामों की चेतावनी दी। मंत्री सरनाईक ने पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि मामले में तत्काल शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी समाज के आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री सरनाईक ने बिल्डरों, गुंडों और असामाजिक तत्वों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा: महाराष्ट्र की धरती पर मराठी लोगों के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कोई न करे। यदि किसी मराठी व्यक्ति को घर देने से इनकार किया गया, तो शिवसेना शैली में जवाब दिया जाएगा।ह्व उन्होंने यह भी बताया कि सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में यदि किसी मराठी परिवार के साथ आवास को लेकर भेदभाव होता है, तो तत्काल मौके पर पहुंचकर जवाब मांगा जाए।

भिवंडी में स्टेम प्राधिकरण जलशुद्धीकरण केंद्र के पास भंगार गोदाम में लगी भीषण आग

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी-ठाणे और मीरा-भाईंदर महानगरपालिकाओं को पानी सप्लाई करने वाले टेमघर स्थित स्टेम प्राधिकरण जलशुद्धीकरण केंद्र के समीप खुले मैदान में बने एक भंगार गोदाम में शुक्रवार शाम भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार गोदाम में बड़ी मात्रा में लकड़ी का सामान, प्लास्टिक ड्रम, बैटरियां और अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे। इसी कारण आग तेजी से फैल गई और धुएं व आग की लपटें आसमान तक दिखाई देने लगीं। घटना की सूचना मिलते ही भिवंडी अग्निशमन दल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को नियंत्रित कर लिया। मौके पर शांतिनगर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड़, प्रभाग समिति क्रमांक-2 के प्रभाग अधिकारी विनोद मनोरे तथा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। विशेष बात यह रही कि यह कबाड़ गोदाम स्टेम प्राधिकरण के जल शुद्धीकरण केंद्र की सुरक्षा दीवार से सटा हुआ था। यदि आग की चपेट में वहां की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था आ जाती, तो भिवंडी, ठाणे और मीरा-भाईंदर शहरों में बड़ा जलसंकट उत्पन्न हो सकता था।सौभाग्य से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड़ ने बताया कि संबंधित जमीन मालिक और भंगार गोदाम संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा गोदाम को तत्काल बंद कराया जाएगा।

उत्तरशक्ति

* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।

पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

मीरा भायंदर में नाला सफाई घोटाला, करोड़ों खर्च फिर भी मजदूर असुरक्षित

600 रुपए में जान जोखिम में डाल रहे श्रमिक – नाला सफाई पर भड़कीं समाजसेविका भावना तिवाड़ी

उदयभान गुप्ता

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा भायंदर महानगरपालिका क्षेत्र में मानसून पूर्व चल रहे नाला सफाई कार्य अब गंभीर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। सफाई कार्यों की गुणवत्ता, मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था और करोड़ों रुपये के टेंडरों में पारदर्शिता को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध तेज हो गया है। समाजसेविका भावना तिवाड़ी ने मनपा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्राप्त करारनामा और कायार्देश के दस्तावेजों के अनुसार, मानसून पूर्व नाला सफाई, खुदाई और गाद निकालने के कार्य के लिए ह्लआशापुरा कंस्ट्रक्शन कंपनीह्व को ठेका दिया गया है। दस्तावेजों में कंपनी के ठेकेदार के रूप में नारायण सिंह का नाम सामने आया है। कंपनी को जेसीबी, पोकलेन मशीन, डम्पर, टोरस, हायड्रा मशीन तथा मजदूर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दस्तावेजों के अनुसार ह्लमैन पावरह्व के लिए लगभग ?1241 प्रति मजदूर प्रतिदिन (8 घंटे) की दर मंजूर दिखाई गई है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर मजदूरों को केवल 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। यह श्रम कानूनों और करारनामा शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है। करारनामा में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मजदूरों को हैंडग्लव्स, गमबूट, मास्क, हेलमेट सहित सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। साथ ही दुर्घटना की स्थिति में उपचार और चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करना भी ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कई स्थानों पर मजदूर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के नालों में उतरकर सफाई करते दिखाई दे रहे हैं। भावना तिवाड़ी का आरोप है कि करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद नालों की सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर नालों से निकाली गई गाद और कचरे को कई दिनों तक सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है, जिससे दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। उनका कहना है कि यह पूरी कार्यप्रणाली सर्वोच्च न्यायालय और बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों की भावना के विपरीत है। न्यायालयों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नालों और सीवर की सफाई अधिकतम मशीनीकृत तरीके से की जाए तथा किसी भी परिस्थिति में बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों को नालों या सीवर में उतारना गैर-कानूनी माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि किसी ठेकेदार या एजेंसी द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है, तो संबंधित ठेका रद्द कर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। समाजसेविका भावना तिवाड़ी ने मनपा आयुक्त और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि आशापुरा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए गए नाला सफाई कार्य, मजदूरों के भुगतान, सुरक्षा व्यवस्था तथा पूरी टेंडर प्रक्रिया की किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, श्रम कानून उल्लंघन या सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मजदूरों की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और नाला सफाई कार्य में अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या मीरा-भाईंदर मनपा प्रशासन संबंधित ठेकेदार नारायण सिंह की कंपनी ह्लआशापुरा कंस्ट्रक्शन कंपनीह्व के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकलिस्ट करेगा, या फिर करोड़ों रुपये के इस पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया जाएगा।

बोईसर बस डिपो पर आयोजित अनुश्री फाउंडेशन का छाछ वितरण कार्यक्रम संपन्न

पालघर (उत्तरशक्ति)। जिले के बोईसर शहर अंतर्गत स्थित बोईसर बस डिपो पर बुधवार 27 मई को अनुश्री फाउंडेशन के द्वारा छाछ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर पुष्पा तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, विद्या राजपूत, जिला अध्यक्ष सुभाष पांडेय, शहर सचिव रूबी सिंह सहित अन्य सदस्य संगीता सिंह, ज्ञानमती निषाद, आरती तिवारी, प्रीति मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा जिला अध्यक्ष आर.बी. सिंह भी मौजूद रहे।

इसके अलावा, सपना उपाध्याय, किरण यादव, मिंटू शर्मा और अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी इस सामाजिक सेवा में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्मी के मौसम में लोगों को शीतल और पौष्टिक पेय उपलब्ध कराना था। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और फाउंडेशन द्वारा समाज सेवा के लिए उठाए गये कदम की प्रशंसा की।

ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन

- घोड़े पर सवार होकर बांटी चॉकलेट
- कल्याण स्टेशन से तहसील कार्यालय तक निकाला मार्च

चेतन निर्मल

कल्याण (उत्तरशक्ति)। देशभर में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में कल्याण में कांग्रेस कार्यकताओं ने अनोखे अंदाज में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बतादें की कल्याण कांग्रेस जिलाअध्यक्ष नवीन सिंह के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकताओं ने कल्याण स्टेशन परिसर में जोरदार आंदोलन किया। इस दौरान कार्यकताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई के मुद्दे पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन को खास बनाने के लिए जिला अध्यक्ष नवीन सिंह घोड़े पर सवार होकर स्टेशन परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने आम नागरिकों को मेलोडी चॉकलेट बांटी। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि यह प्रदर्शन आम आदमी पर बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के बोझ के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकताओं ने घोड़े पर सवार होकर कल्याण स्टेशन परिसर से तहसील कार्यालय तक मार्च निकाला। पूरे रास्ते भाजपा सरकार होश में आओ, महंगाई कम करो और पेट्रोल-डीजल के दाम वापस लो जैसे नारों से माहौल गूंजता रहा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं इस अनोखे प्रदर्शन ने आम लोगों और मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर व रायटर राज नरेन्द्र का भिवंडी में किया गया भव्य स्वागत

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी के पद्मानगर स्थित श्रीरंगनगर परिसर के विराज रेसीडेंसी में समाजसेवक गोपी मार्गम के आवास पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध डायरेक्टर व रायटर राज नरेन्द्र का भव्य सत्कार दादा साहेब फालके पुरस्कार से किया गया। यह स्वागत समारोह अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी के स्वीकृत सदस्य तथा महाराष्ट्र राज्य पद्मशाली संगम के प्रसिद्धि प्रमुख श्रीनिवास सिरीमल्ले के नेतृत्व में आयोजित किया गया ।बताया जा रहा है कि राज नरेन्द्र इन दिनों मुंबई प्रवास पर हैं और इसी क्रम में वे भिवंडी पहुंचे, जहां समाज के लोगों एवं फिल्म प्रेमियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राज नरेन्द्र ने अपने फिल्मी सफर के अनुभव साझा करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और क्षेत्रीय फिल्मों को भी देशभर में बड़ी पहचान मिल रही है। राज नरेन्द्र के निर्देशन में अब तक कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है, जिनमें चर्चित फिल्म खलवीवनम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी फिल्मों की कहानी, निर्देशन शैली और सामाजिक विषयों को दर्शकों ने काफी सराहा है ।इस अवसर पर तेलंगाना से आए रायटर चिंदम मल्लेशम पाली, पत्रकार लवलेश सुतार, आचार्य सूरजपाल यादव, हर्षवर्धन सब्बानी सहित अनेक गणमान्य नागरिक, समाजसेवक एवं फिल्म प्रेमी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने राज नरेन्द्र को शॉल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का वातावरण काफी उत्साहपूर्ण रहा तथा उपस्थित लोगों ने भविष्य में भिवंडी में सांस्कृतिक एवं फिल्म संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी चर्चा की।

आल्डेल हाई स्कूल ने एसएससी बोर्ड परीक्षा में हासिल किया 100% परिणाम

पालघर (उत्तरशक्ति)। पालघर क्षेत्र के तेजी से उभरते और विश्वसनीय स्कूलों में शामिल आल्डेल हाई स्कूल ने अपनी पहली दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ ररउ बोर्ड परीक्षा 2025-26 में 100% सफलता हासिल कर एक नई मिसाल कायम की है। यह उपलब्धि स्कूल की उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता और समर्पित शिक्षण पद्धति का परिणाम है।

आल्डेल एजुकेशन ट्रस्ट के नेतृत्व में स्थापित यह विद्यालय प्रतिष्ठित सेंट जॉन टेक्निकल एंड एजुकेशनल कैंपस में स्थित है और अपने प्रेरक ध्येयवाक्य ह्लअर्श्री, ईटीपी, आॅपीह्व को सार्थक रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2007 में संस्थापक-अध्यक्ष अल्बर्ट डब्ल्यू डिसूजा द्वारा की गई थी।

आज यह ट्रस्ट प्री-प्राइमरी से स्नातकोत्तर व्यावसायिक शिक्षा तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला एक सशक्त शैक्षणिक समूह बन चुका है। विद्यालय न केवल शैक्षणिक विकास बल्कि विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर विशेष ध्यान देता है। यहाँ आधुनिक कक्षाएँ, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर शिक्षा, खेल सुविधाएँ, कराटे, अबेकस और विभिन्न व्यक्तित्व विकास गतिविधियाँ उपलब्ध हैं। प्रधानाचार्या सिस्टर लिंडा रोड्रिग्स ने इस शानदार उपलब्धि पर विद्यार्थियों, मेरिट सूची में शामिल छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और प्रबंधन को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता छात्र-केंद्रित शैक्षणिक योजना, नियमित मूल्यांकन और प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान का परिणाम है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नर्सरी से कक्षा दसवीं तक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आल्डेल हाई स्कूल की खासियत यह भी है कि विद्यार्थी दसवीं के बाद भी इसी परिसर में अपनी उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा निरंतर जारी रख सकते हैं।

सेंट जॉन टेक्निकल एंड एजुकेशनल कैंपस में संचालित अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं में सेंट जॉन इंटरनेशनल स्कूल (उइरए), सेंट जॉन जूनियर कॉलेज, सेंट जॉन कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेज, सेंट जॉन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सेंट जॉन इंस्टिट्यूट ऑफ फामेर्सी एंड रिसर्च, आल्डेल कॉलेज ऑफ फामेर्सी एंड रिसर्च और आल्डेल इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शामिल हैं, जो विद्यार्थियों को एक ही विश्वसनीय परिसर में उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं।

डोंबिवली खंबाळपाडा-कांचनगांव हत्याकांड का आरोपी तीन दिन बाद गिरफ्तार

- टिळकनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कल्याण से आरोपी रोहित शेलार गिरफ्तार

डोंबिवली (उत्तरशक्ति)। डोंबिवली पूर्व के खंबाळपाडा-कांचनगांव इलाके में घर निर्माण को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी रोहित शेलार को आखिरकार टिळकनगर पुलिस ने तीन दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर कल्याण परिसर से आरोपी को हिरासत में लेकर बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक, यह सनसनीखेज घटना मंगलवार शाम करीब पांच बजे खंबाळपाडा इलाके में हुई थी। मृतक प्रताप चौधरी और

आरोपी रोहित शेलार पड़ोसी थे। दोनों के बीच घर के निर्माण कार्य को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। प्रताप चौधरी ने रोहित शेलार के निर्माण कार्य को लेकर शिकायत की थी। इसी शिकायत के कारण घर तैयार होने के बावजूद रोहित को किराए के मकान में रहना पड़ रहा था, जिससे दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मंगलवार को दोनों के बीच विवाद फिर भड़क उठा। आरोप है कि गुस्से में रोहित शेलार प्रताप चौधरी के घर में घुस गया और धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में प्रताप चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए टिळकनगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। लगातार तीन दिनों तक की गई खोजबीन और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने शुक्रवार दोपहर करीब चार बजे कल्याण इलाके से आरोपी रोहित शेलार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर 1 से 5 जून तक चलेगा स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु अभियान

पालघर(उत्तरशक्ति)। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर महाराष्ट्र शासन के जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 1 जून से 5 जून 2026 तक राज्यभर में ₹ स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु ₹ विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर व्यापक जनजागरूकता फैलाना है। जिला परिषद पालघर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने जिले के सभी ग्राम पंचायतों से इस अभियान को प्रत्येक गांव में प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की है।

इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इनमें घनकचरा प्रबंधन नियम 2026 के प्रति जागरूकता, गांवों की स्वच्छता सुविधाओं का मूल्यांकन, अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले स्त्रोतों की पहचान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान तथा विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन शामिल रहेगा। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के चार श्रेणियों में वर्गीकरण (4फप्रणाली), घर-घर कचरा संकलन व्यवस्था, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और पुराने कचरा डंप स्थलों के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया जायेगा। साथ ही नागरिकों को जल संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचाव, कचरा कम करने और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। अभियान के तहत 4 जून को जनजागरूकता रैली, प्रभात फेरी, चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, महिला बचत समूह संवाद कार्यक्रम तथा ह्ल एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इन उपक्रमों में युवाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों, स्वच्छाग्रहियों और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। वहीं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष ग्रामसभाएं आयोजित कर अभियान की समीक्षा की जायेगी। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर जनसहभागिता के माध्यम से स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है।

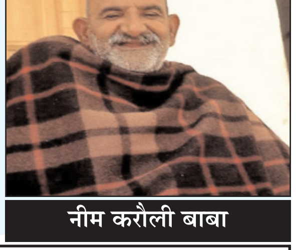
नीम करौली बाबा

जिला परिषद पालघर में मनाई गई स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती

सीईओ मनोज रानडे ने प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर किया नमन

पालघर(उत्तरशक्ति)। जिला परिषद पालघर में गुरुवार को महान क्रांतिकारी, विचारक एवं समाज सुधारक स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने सावरकर की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में स्वातंत्र्यवीर सावरकर के राष्ट्रनिर्माण, स्वतंत्रता संग्राम तथा सामाजिक सुधारों में दिए गये महत्वपूर्ण योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी क्रांतिकारी, प्रखर विचारक, साहित्यकार और समाज सुधारक थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। अंदमान की सेल्युलर जेल में कठोर यातनाएं सहने के बावजूद उनका राष्ट्रप्रेम और संघर्ष का जज्बा कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा को नई दिशा देने के साथ-साथ सामाजिक समता, वैज्ञानिक सोच और जातिभेद उन्मूलन के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किए। मराठी साहित्य में भी कविता, नाटक और लेखन के माध्यम से उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी व्यंकटराव हुंडेकर सहित जिला परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरा, छह मजदूरों की मौत

बेतवा नदी पर चल रहा था निर्माण कार्य, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। बेतवा नदी पर बन रहे एक निमार्णाधीन पुल का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई।

जानकारी के अनुसार, हादसे में अब तक छह मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य मजदूरों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव टीम मौके पर पहुंच गईं।

एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमों द्वारा युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा

है। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

हादसे के बाद जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। शुरूआती तौर पर निर्माण कार्य में तकनीकी खामी या लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।

सैलून में युवक पर जानलेवा फायरिंग, बाल-बाल बची जान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के मेढ़ा मोड़ स्थित एक सैलून में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में युवक बाल-बाल बच गया, जबकि हमलावर फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार आशीष मिश्रा नामक युवक सैलून में शेविंग करा रहा था। इसी दौरान बाइक से पहुंचे नकाबपोश बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। अचानक हुई फायरिंग से सैलून में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि गोली युवक को नहीं लगी और उसकी जान बच गई।

घटना की सूचना मिलते ही सिंगरामऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में पुराने विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है। दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करेंगे अखिलेश यादव: अरशद खान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, भारत किसान यूनियन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा एवं ह्यभारत रत्नह्व चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि भारत के गांव, किसान, मजदूर और गरीब वर्ग की आवाज थे। उन्होंने जीवनभर किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया।

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का सपना था कि भारत की पहचान केवल जनसंख्या से नहीं बल्कि कृषि शक्ति से हो। वे चाहते थे कि भारत का किसान आर्थिक रूप से इतना मजबूत बने कि दुनिया के विकसित देशों के किसान भी उसकी प्रगति का उदाहरण दें। उन्होंने हमेशा यह माना कि यदि गांव मजबूत होंगे, किसान खुशहाल होंगे और कृषि समृद्ध होगी, तभी भारत वास्तविक अर्थों में विश्व शक्ति बन सकेगा।

उन्होंने कहा कि आज देश का किसान आर्थिक संकट, बढ़ती लागत, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सरकारी उपेक्षा से परेशान है। किसानों की आय बढ़ाने के बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीन पर किसानों की स्थिति लगातार कमजोर हुई है। खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है और युवा खेती छोड़ने को

मजबूर हो रहे हैं।

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का स्पष्ट मानना है कि किसानों और मजदूरों के बच्चों को उच्च शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए तथा किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि समाजवादी सोच हमेशा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। अखिलेश यादव जी की नीतियां किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने, युवाओं को रोजगार देने, गरीबों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने और सामाजिक सौहार्द कायम करने की दिशा में केंद्रित हैं।

मोहम्मद अरशद खान ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनकर किसानों, मजदूरों, नौजवानों तथा कमजोर वर्गों के लिए नई विकास योजनाओं को लागू करेंगे। किसानों की कर्ज समस्या, सिंचाई, बिजली, खाद-बीज, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह का सपना केवल किसानों की खुशहाली नहीं था, बल्कि ऐसा भारत बनाना था जहां गांव आत्मनिर्भर हों, शिक्षा सबको मिले, बेरोजगारी समाप्त हो और सामाजिक न्याय की स्थापना हो। समाजवादी पार्टी इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है।

अंत में मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के आदर्श आज भी देश के लिए मार्गदर्शक हैं और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए किसानों, मजदूरों, युवाओं और सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को एकजुट होकर आगे आना होगा।

न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग, कोलेजियम सिस्टम खत्म करने की उठी आवाज

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक जौनपुर सदर मोहम्मद अरशद खान ने देश की मौजूदा न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम जनता को समय पर और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था इतनी महंगी और जटिल हो चुकी है कि गरीब और ग्रामीण लोगों के लिए न्याय पाना कठिन होता जा रहा है।

पीडीए भवन कटघरा में आयोजित प्रेस वार्ता में मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि 'देर से मिला न्याय, न्याय नहीं माना जा सकता।' उन्होंने न्याय व्यवस्था को सस्ता, सुलभ और समयबद्ध बनाने के लिए कई बड़े सुधारों की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ आबादी के लिए केवल दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। इसलिए देश के सभी राज्यों की राजधानियों में सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित की जानी चाहिए। साथ ही प्रत्येक कमिश्नरी मुख्यालय पर हाईकोर्ट की बेंच तथा तहसील स्तर तक मुंसिफ अदालतें स्थापित की जाएं ताकि ग्रामीण और गरीब जनता को स्थानीय स्तर पर न्याय मिल सके।

मोहम्मद अरशद खान ने 'जस्टिस विदिन वन ईयर' कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि मुकदमों को चार श्रेणियों में बांटकर तीन महीने, छह महीने, नौ महीने और एक वर्ष के भीतर फैसला देने की समय सीमा तय होनी चाहिए। कोलेजियम सिस्टम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में कई नियुक्तियां रिश्तेदारी और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर होती हैं, जिससे निष्पक्ष न्याय की भावना प्रभावित होती है। उन्होंने कोलेजियम सिस्टम समाप्त करने की मांग की। उन्होंने न्यायपालिका में दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ाने की भी मांग की। उनका कहना था कि आबादी के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था लागू कर सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि इन मांगों को लेकर वह पहले भी आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर चुके हैं तथा जल्द ही दिल्ली में एक बड़े धरने का आयोजन किया जाएगा।

शाही ईदगाह में शांतिपूर्ण संपन्न हुई ईद-उल-अजहा की नमाज, इमाम ने बताया कुबार्नी का महत्व

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मछलीशहर पड़ाव स्थित शाही ईदगाह में ईद-उल-अजहा (बकरीद) की नमाज पूरी अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न हुई। शाही ईदगाह के इमाम एवं खतीब हजरत मौलाना अब्दुज जाहिर सिद्दीकी हम्फी ने हजारों नमाजियों को नमाज अदा करवाई।

हजरत इब्राहीम की सुन्नत (इतिहास) मौलाना अब्दुज जाहिर सिद्दीकी ने अपने खुतबे (भाषण) में बताया कि कुबार्नी की शुरूआत अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से हुई। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम के जज्बे को आजमाने के लिए उनकी सबसे प्रिय चीज–उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुबार्नी मांगी थी। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सिर झुका दिया। जब वे अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने लगे, तो अल्लाह ने उनके इस समर्पण को कुबूल कर लिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वहां एक दुम्बा (नर भेड़) भेज दिया। बेटे की जगह उस दुम्बे की कुबार्नी हुई। इसी महान समर्पण की याद में पिछले पांच हजार साल से हर साल बकरीद मनाई जाती है।

उन्होंने आगे कहा कि नमाज हमेशा ईदगाह में पढ़े ताकि मुसलमानों के शानो शौकत का इजहार हो। ईदगाह में नमाज पढ़ना खुले मैदान में ईद और ईद उल अजहा की नमाज पढ़ना सुन्नत है।

कुबार्नी क्यों और कैसे हो (इस्लामी और कानूनी तरीका) इमाम साहब ने खुतबे में जोर दिया कि कुबार्नी केवल एक रस्म नहीं, बल्कि अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुबार्न करने का जज्बा है। लोगों ने अपनी आर्थिक हैसियत के अनुसार हलाल कमाई से खरीदे गए जानवरों की कुबार्नी दी।

कुबार्नी करने का सही तरीका

जानवर की सेहत: जानवर पूरी तरह स्वस्थ, तंदुरुस्त और बिना किसी शारीरिक ऐब (जैसे अंधापन, लंगड़ापन) के होना चाहिए।

तीन हिस्से: कुबार्नी के गोश्त के तीन बराबर हिस्से किए जाते हैं–एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों व पड़ोसियों के लिए और तीसरा हिस्सा खुद के परिवार के लिए।

साफ-सफाई का ध्यान: प्रशासन के निर्देशों के तहत कुबार्नी सार्वजनिक रास्तों या खुले स्थानों पर करने से बचें।

अवशेषों का निस्तारण: कुबार्नी के बाद बचे हुए अवशेषों और गंदगी को खुले में न फेंकें, बल्कि उन्हें गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबाएं या नगर पालिका के कचरा वाहनों को सौंपें।

सोशल मीडिया पर पाबंदी: किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुबार्नी न करें और न ही कुबार्नी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, जिससे किसी की भावनाएं आहत हों।

मुस्तैद अफसर: शासन की मंशा के अनुरूप सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे रहे।

पंडाल पर जोर: मुख्य विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता ईदगाह के बाहर लगे पंडालों पर नमाजियों का स्वागत करते और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आए।

उत्साहित बच्चे: त्योहार को लेकर बच्चों में भारी उत्साह दिखा, वे नए कपड़ों में एक-दूसरे से गले मिलते नजर आए।

इस मौके पर मुख्य रूप से नेयाज ताहिर शेखू, मोहम्मद शोएब अच्छू खान, जफर राजा, रियाजुल हक, हाजी इमरान खान, मौलाना आफाक, अकरम मंसूरी आदि मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट, हर तरफ जंगलराज: डा.प्रमोद कुमार सिंह

सरकार के मंत्री, विधायकों की संपत्तियों की जांच किए जाने और खास्ता कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के विधायक, मंत्री और सत्ताधारी दल के नेता आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकारी धन और जनता के पाकेट पर खुलेआम लूट अब सरकारी नियम बन गया है, सरकार के जनविरोधी नीतियों से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। उक्त बातें कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष डा प्रमोद कुमार सिंह ने शुक्रवार को शहर के एक होटल में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा। डा. प्रमोद कुमार सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ उनकी संपत्तियों की जांच की मांग करने वाले भाजपाइयों, भाजपा के विधायकों और मंत्रियों के भी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, सरकारी धन की लूट इस सरकार का फैशन बन गया है। डा. प्रमोद कुमार सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी संघर्षशील और इमानदार व्यक्ति हैं,उनकी स्वच्छ और इमानदार छवि तथा उनकी बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा के लोग डरे हुए हैं। पेपर लीक , डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और मंहगाई और प्रदेश में प्रतिदिन हो रही हत्या, बलात्कार की घटनाओं से ध्यान भटकाने के लिए अजय राय जी के खिलाफ मुकदमा

दर्ज कराया गया है, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों और महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस नेता डा.प्रमोद कुमार सिंह ने मांग करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई को भाजपा नेताओं की जांच करनी चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि इनकी संपत्तियों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और सरकार के लोगों ने जनता के धन को लूटकर कितनी संपत्तियां बनाई है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है, अब तक नीट सहित कुल अस्सी परीक्षाओं केप्रश्नपेपर लीक हो चुका है, बहुत से अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर लिया, बेतहाशा महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार पूरी तरह फेल हो गयी है, उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर पहुंच गया है। हत्या, बलात्कार, डकैती और छिनैती की बढ़ती घटनाओं से लोगों में भय पैदा हो गया है। आरिफ खान ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता मुख्य रूप से संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा,लाल प्रकाश पाल, शहनवाज मंजूर,अनिल सोनकर, इरशाद खान राजू, इकबाल हुसैन, दिवाकर मौर्या, परवेज अहमद,मुहम्मद ताहिर, तौफीक अहमद, सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

तीन नन्हीं किलकारियों से गूंजा जौनपुर

हाई-रिस्क ट्रिपलेट डिलीवरी में डॉक्टरों ने रचा नया कीर्तिमान

प्रियेश गुप्ता रुद्रा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद के नईगंज स्थित राजकुमार सिंह मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने एक बेहद जटिल और हाई-रिस्क केस को सफलतापूर्वक संभालते हुए मां और तीन नवजात बच्चों की जान बचाकर चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस सफलता के बाद अस्पताल और चिकित्सकों की टीम की पूरे क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय महिला लगभग 33 सप्ताह की ट्रिपलेट प्रेग्नेंसी यानी तीन बच्चों की गर्भावस्था से गुजर रही थीं। मरीज गंभीर एनीमिया से भी पीड़ित थीं और उनका हीमोग्लोबिन मात्र 6.4 था। इसके अलावा महिला के पहले से दो सिजेरियन ऑपरेशन (छरज) हो चुके थे, जिससे तीसरी बार ऑपरेशन करना बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा माना जा रहा था।

मरीज की हालत को देखते हुए अस्पताल की विशेषज्ञ टीम ने बिना समय गंवाए आपातकालीन ऑपरेशन का निर्णय लिया। अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक तीसरा छरज ऑपरेशन कर तीन प्रीमैच्योर बच्चों की सुरक्षित डिलीवरी कराई। डॉक्टरों की सतर्कता, अनुभव और बेहतर टीमवर्क के चलते मां और तीनों नवजात पूरी तरह सुरक्षित एवं स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

इस जटिल ऑपरेशन में डॉ. आनंद सिंह, डॉ. राजेश त्रिपाठी, डॉ. प्रियमवदा सिंह तथा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. डी.के. यादव की अहम भूमिका रही। अस्पताल प्रशासन ने इसे चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी सफलता बताया है।

स्थानीय लोगों ने भी डॉक्टरों की टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह जौनपुर के लिए गर्व का क्षण है, जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की बदौलत इतना कठिन ऑपरेशन सफलतापूर्वक संभव हो सका।

जौनपुर में शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ ईद उल अजहा का पर्व

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद में ईद उल अजहा (बकरीद) का पर्व गुरुवार को सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। पर्व के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने प्रमुख मार्गों पर भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से संवाद कर उन्हें ईद उल अजहा की शुभकामनाएं भी दीं।

पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पूरे जनपद को 07 सुपर जोन, 28 जोन एवं 156 सेक्टरों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र में सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट तथा जोनल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी, जिन्होंने लगातार भ्रमण कर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखी।

जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुबार्नी के बाद अवशेषों का समुचित निस्तारण कराया जाए तथा साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक शहरी आयुष श्रीवास्तव, सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता, प्रशिक्षु आईपीएस सृष्टि जैन, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परमानंद झा, नगर मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की जलकर मौत, हत्या की आशंका से सनसनी

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। तेजी बाजार थाना क्षेत्र के कान्हापुर स्थित चौबान बस्ती में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अशोक मिश्रा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों द्वारा युवक को कथित रूप से जलाकर मार डाले जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया तथा मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर तेजी बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

बेशकीमती जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप, डीएम से लगाई गुहार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के भौराजीपुर स्थित सिपाह पुलिस चौकी के बगल में स्थित करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया है। जमीन मालिकों ने भू माफियाओं पर पुलिस की मिलीभगत से जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पूजा यादव, मुख्तार अहमद और धर्मेंद्र मौर्य ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उक्त जमीन उनकी है, जिस पर बाउंड्रीवाल और गेट लगा हुआ है। आरोप है कि 25 मई को कुछ लोगों ने गेट का ताला तोड़कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पीड़ितों का कहना है कि कई बार अवैध कब्जे का प्रयास किया जा चुका है, जिसकी शिकायत एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सिपाह मोहल्ले के कुछ दबंग और कथित प्लाटर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज नहीं है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और जिले के उच्च अधिकारियों से करते हुए पीड़ितों ने कब्जे के प्रयास पर रोक लगाने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है।

हंडिया में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की टक्कर में तीन की मौत

प्रयागराज (उत्तरशक्ति)। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और कार के बीच हुई भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार कार सवार लोग ज्ञानपुर से झूंसी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हंडिया क्षेत्र में सामने से आ रही रोडवेज बस से उनकी कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।

अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने रवि यादव के परिजनों से की मुलाकात

जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

खेतासराय, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने थाना खेतासराय क्षेत्र के सोंधी गांव पहुंचकर चर्चित आजाद बिंद दूल्हा हत्याकांड के नामजद सह आरोपी रवि यादव के परिजनों से मुलाकात की तथा पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की।

मुलाकात के दौरान परिजनों ने बताया कि रवि यादव बी.कॉम तक शिक्षित था और उसका कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं था। परिवार के अनुसार उसके खिलाफ केवल दो छोटे मुकदमे दर्ज थे। परिजनों ने पुलिस इनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की किसी न्यायिक अधिकारी अथवा जज

से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जल्द सौंपेंगे, ताकि मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित हो सके।

गौरतलब है कि 24 मई की रात पुलिस मुठभेड़ में रवि यादव घायल हुआ था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद से क्षेत्र में मामले को लेकर चचाओं का माहौल बना हुआ है। वहीं परिजन लगातार न्यायिक जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

हुक्का बार चलाना मौलिक अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज की

लखनऊ (उत्तरशक्ति)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हुक्का बार संचालकों को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि हुक्का बार चलाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ऐसे कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने एम्पेरियो ग्रैंड प्राइवेट लिमिटेड समेत कई हुक्का बार संचालकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाओं में प्रशासनिक कार्रवाई, प्रतिष्ठानों को बंद कराने तथा नए लाइसेंस न देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हुक्का बारों में

तंबाकू और निकोटीन का सेवन कराया जाता है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। अदालत ने इसे सामान्य व्यापारिक गतिविधियों से अलग श्रेणी में रखते हुए कहा कि सरकार को जनहित में ऐसे कारोबार पर रोक लगाने का अधिकार है।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में हुक्का बारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। फैसले को जनस्वास्थ्य की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

मुंगरा बादशाहपुर नगर अध्यक्ष कपिल मुनि को तीन वर्ष पूर्ण होने पर जोरदार स्वागत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मुंगरा बादशाहपुर के नगर पालिका अध्यक्ष कपिल मुनि का तीन वर्ष का सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर उनका स्वागत सृष्टि पैलेस हॉल में सुंदर काण्ड पाठ के साथ बड़े धूमधाम से मनाया गया और प्रीतिभोज का भी आयोजन किया गया था। हॉल में नगर पालिका के सभी सदस्य गण उपस्थित थे। कपिल मुनि भाजपा के समर्थक हैं । कपिल मुनि का समाज कल्याण कार्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है । वे एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे सदा सहज भाव से समाज कार्य में अपना योगदान किया करते रहते है जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर में समजिक कार्य में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कपिल मुनि का जीवन एक खुली किताब के समान है। वे अपने जीवन में सदैव मानव सेवा में पुरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। मुंगरा बादशाहपुर को स्वच्छ और स्वस्थ , सुंदर बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। उस शुभ अवसर पर प्रशांत मिश्रा, अमित गुप्ता, राजू दुबे (गीता दुबे वेल्डिंग कंपनी संचालक), आशिष गुप्ता, अयोध्या तिवारी (नई बाजार), दैनिक उत्तर शक्ति समाचार पत्र के उपसंपादक प्रेम चंद मिश्रा, कृष्ण चंद्र दुबे ,रवि दुबे , पत्रकार विष्णु कांत मिश्रा सहित कई लोगों ने तीन वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

झुलसाती गर्मी में मानवता की मिसाल बना वाराणसी व्यापार मंडल

-रिक्शा चालकों, दिव्यांगों और मजदूरों को बांटे गमछा, धूप का चश्मा व पानी

सुरेश गांधी

वाराणसी। भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच जहां आम जनजीवन बेहाल है, वहीं सामाजिक सरोकारों को लेकर वाराणसी व्यापार मंडल ने एक संवेदनशील पहल करते हुए जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का कार्य किया। वाराणसी व्यापार मंडल एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सेवा कार्यक्रम के तहत रिक्शा चालकों, टॉली चालकों, दिव्यांगजनों तथा राह चलते मजदूरों को धूप से बचाव के लिए चश्मा, गमछा और शीतल पेयजल वितरित किया गया।

कार्यक्रम का नेतृत्व वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्घा ने किया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को होती है, जो पूरे दिन सड़क पर मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। ऐसे लोगों की सहायता करना समाज का दायित्व है। सेवा सामग्री प्राप्त कर रिक्शा चालकों और मजदूरों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कई रिक्शा चालकों ने भावुक होकर कहा कि आज तक किसी ने उनकी तकलीफों को इस तरह महसूस नहीं किया। वाराणसी व्यापार मंडल ने जिस आत्मीयता के साथ उनकी मदद की है, वह सराहनीय और प्रेरणादायी है। उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद भी दिया।

इस दौरान पूरा क्षेत्र सेवा, संवेदना और सामाजिक समरसता के भाव से सराबोर दिखाई दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में मानवता और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सत्य प्रकाश जायसवाल, शाहिद कुरैशी, सुजीत वर्मा, प्रिंस, दिलीप, आशीष शर्मा, प्रिया अग्रवाल, संगीता चौबे, सुनील चौरसिया, रवि चौरसिया, महेश चौरसिया, रमेश चौरसिया, उमा यादव, किशोरी दुबे, बिंदु सिंह, रोहित सिंह, भावना सिंह, प्रियम प्रगा तिवारी, समीर यादव, अनिकेश निगम, साहिल यादव, अमरनाथ चौरसिया, सूजीत चौरसिया सहित बड़ी संख्या में व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बढ़ती मांग के बीच आईओसी द्वारा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति जारी

मुंबई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश के विभिन्न क्षेत्रों में ईंधन की बढ़ती मांग के बीच पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपने संचालन और लॉजिस्टिक समन्वय को लगातार जारी रखे हुए है। हाल के दिनों में,नीचे दिये गए टेबल के अनुसार,इंडियनऑयल ने पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह बढ़ी हुई मांग विभिन्न कारणों से प्रेरित है, जैसे ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में मौसमी जुताई और कटाई गतिविधियाँ। इसके अलावा, पीएसयू के अलावा अन्य आपूर्तिकताओं के मूल्य अंतर के कारण ग्राहकों का रुझान सार्वजनिक क्षेत्र के रिटेल आउटलेट्स की ओर बढ़ा है। साथ ही, संस्थागत और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के रिटेल ईंधन आउटलेट्स की ओर स्थानांतरण के कारण अतिरिक्त मांग भी उत्पन्न हुई है। इंडियनऑयल अपने व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क –टर्मिनल्स,डेपो,पाइपलाईन्स,एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स और रिटेल आउटलेट्स – के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए है। आपूर्ति टीमें, परिवहन नेटवर्क, टर्मिनल संचालन और चयनित रिटेल आउटलेट्स बाजारों में निर्बाध उत्पाद आवाजाही और समय पर पुनःपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे कार्यरत हैं। निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इंडियनऑयल राज्य प्रशासन के साथ भी निकट समन्वय बनाए हुए है। इंडियनऑयल उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना चाहता है कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सुचारु एवं निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे सामान्य खरीद व्यवहार जारी रखें और घबराहट में खरीदारी से बचें। उपभोक्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे ईंधन उपलब्धता से संबंधित सही जानकारी के लिए केवल इंडियनऑयल की अधिकृत एजेंसियों द्वारा जारी आधिकारिक संचार पर ही भरोसा करें।

दीप यज्ञ और श्रद्धांजलि गीतमाला के साथ मनाई ग्रापए के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की पुण्यतिथि

-अमित सिंह

बेंगलुरु (उत्तरशक्ति)। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की 39वीं पुण्यतिथि ब्रिगेड पार्क साइड ईस्ट के सभागार में दीप यज्ञ और श्रद्धांजलि गीतमाला के साथ मनाई गई। मुख्य अतिथि गायत्री परिवार कर्नाटक के कोऑर्डिनेटर शेखर चतुर्वेदी ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं प्रकाशित कर शासन तक पहुंचाने में ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि योगेंद्र अग्रहरि ने पुष्पांजलि अर्पित की। विशेष आमंत्रित अतिथि गोपाल अग्रवाल एवं शंकर तिवारी ने देव मंच पर मुख्य कलश का पूजन किया। अनुपमा एवं रेखा सक्सेना ने गुरु पूजन व देव पूजन किया। गायत्री गोयल के भक्ति गीतों ने समां बांध दिया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष अतुल कपूर ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को उत्तर प्रदेश के नूरपुर(बिजनौर) में संपन्न हुए पत्रकार सम्मेलन की स्मारिका 'ग्राम्य गौरव' भेंट की। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गोवा के प्रभारी एवं कर्नाटक के कोषाध्यक्ष गोविंद रविशंकर ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गीत प्रस्तुत किया 'ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना'।

अतुल कपूर ने उपस्थित पत्रकारों एवं साहित्य प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबू बालेश्वर लाल जी ने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गडवार से जो दीप प्रज्वलित किया, उसकी किरणें अब दक्षिण भारत के पत्रकारों को भी प्रकाश बांट रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में सात राज्यों में विधिवत प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो चुका है तथा पांच राज्यों के प्रदेश संयोजक मनोनीत किया जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 'जो औरों के हित मरता है जो औरों के हित जीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है।' दीप यज्ञ का संचालन गायत्री चेतना केंद्र की टोली के आचार्य कमलेश खरे, गायत्री गोयल एवं दिलीप गोयल ने किया। वैदिक मत्रों के साथ जब एक साथ सैकड़ो दीप जले तो उस समय अपर्णा द्वारा प्रस्तुत गीत 'ज्योति कलश छलके' अत्यंत सराहनीय रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अंशुल शर्मा, अर्पित दीक्षित, केवल, गोविंद शास्त्री, स्मिता कपूर, सोनाली टंडन, प्रियंका, गीता, पंकज सिंह आनंद कृष्णा, गौरी, वेंकट रमन आदि का विशेष योगदान रहा।

अध्ययन अकैडमी के छात्रों का परिणाम शत प्रतिशत रहा

ठाणे (उत्तरशक्ति)। अध्यन अकैडमी निरंतर प्रगति पर चल रहा है। अकैडमी द्वारा संचालित विद्यार्थियों के उज्वल भविष्य के लिये एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य निरंतर जारी रखे हुए है। बारहवीं ,दसवीं परीक्षा फल महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा घोषित हुआ जिसमें विद्यार्थी शत प्रतिशत उत्तीर्ण हुए ।विद्यार्थियों के परिश्रम के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिये प्रेरित करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया ।वर्ष 2026 का वार्षिक परिणाम घोषित हुआ जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुए विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इसके लिए संचालक सचिन रतन मिश्रा ,धर्मेंद्र चौधरी ,श्रद्धा पडार एवं समीक्षा मिश्रा , एवं डे जी मिश्रा आदि शिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अच्छे अंक प्राप्त करने से छात्रों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।

मधुकर तिवारी के द्वारा बड़े मंगलवार के उपलक्ष्य में जौनपुर में विशाल भंडारा संपन्न

जौनपुर। जेठ माह के पवित्र चतुर्थ बड़े मंगलवार के पुनीत अवसर पर बीआरपी इंटर कॉलेज स्थित श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर के निकट मुक्तेश्वर प्रसाद महाविद्यालय परिसर में वरिष्ठ पत्रकार पीटीआई मधुकर तिवारी, राकेश तिवारी, अनुराग तिवारी सहित पूरे तिवारी परिवार द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पत्रकार आदेश मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम में प्रसाद वितरण एवं भंडारे में वरिष्ठ समाजसेवी ज्ञानप्रकाश सिंह,पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह,कांग्रेसी नेता रोहित सिंह,पत्रकार आई वी सिंह, ऋतु राज सिंह छोटू, वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, समाजसेवी तथा अनेक गणमान्य भक्तगण आयोजन में शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान भक्तों द्वारा जय श्री राम एवं महाबली सरकार हनुमान जी के जयघोष से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। भंडारे के सफल आयोजन की लोगों ने खूब सराहना की। आयोजक मधुकर तिवारी ने कार्यक्रम में पधारे सभी श्रद्धालुओं एवं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

भारत-क्लाउड ने भारत-नॉर्वे बिजनेस एवं रिसर्च समिट में भाग लिया

मंबई। ओस्लो में आयोजित भारत-नॉर्वे बिजनेस एवं रिसर्च समिट के दौरान, भारत-क्लाउड ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तथा भारत और नॉर्वे के बीच तकनीकी सहयोग पर हुई चचाओं में भाग लिया। यह समिट एक ऐसा आयोजन था जहाँ भारत और नॉर्वे दोनों देशों के नीति-निमार्ता, इनोवेटर्स, शोधकर्ता, व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ वैश्विक स्तर पर डिजिटलीकरण के भविष्य को परिभाषित करने वाली संभावनाओं को तलाशने के लिए एकत्रित हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे तथा क्राउन प्रिंस हाकोन ने, 50 से अधिक कंपनियों और भारत-नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान समुदाय के 250 से अधिक प्रतिभागियों के साथ, इस समिट में भाग लिया। यह सहभागिता ऐसे समय में हुई जब भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता पहले से ही आकार ले रहा था और दोनों देशों के बीच इनोवेशन तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने वाला था। भारत-क्लाउड की प्रतिनिधि के रूप में, शीतल श्रीकांत ने संप्रभु क्लाउड इकोसिस्टम, एआई-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा संगठनों द्वारा अपनी एआई यात्रा को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ सुरक्षित क्षेत्रीय डेटा इकोसिस्टम के उभरते महत्व से संबंधित चचाओं में भाग लिया। हालांकि, व्यापक स्तर पर समिट की चचाओं ने यह स्पष्ट किया कि विश्वभर के देश विश्वसनीय डिजिटल संप्रभु एआई-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षित क्लाउड इकोसिस्टम, औद्योगिक डिजिटलीकरण, एआई-आधारित परिवर्तन और सतत तकनीकी साझेदारियों के विकास पर अधिक जोर दे रहे हैं।

भारत-क्लाउड की संस्थापक सदस्य शीतल श्रीकांत ने कहा, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के वर्ष 2029-30 तक देश की राष्ट्रीय आय में लगभग 20% योगदान देने का अनुमान है, जो स्पष्ट रूप से दशार्ता है कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महत्वपूर्ण बन चुका है। प्रस्तावित भारत-नॉर्वे ब्रिज जैसी पहलें दोनों देशों के स्टार्टअप्स, निवेशकों और अनुसंधान इकोसिस्टम के बीच सहयोग को मजबूत कर सकती हैं, जिससे डीप टेक, एआई, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और औद्योगिक डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में नए अवसर उत्पन्न होंगे।

SOTC ट्रैवल ने भारत और विदेशों में वर्षभर के आध्यात्मिक यात्राओं का कैलेंडर तैयार किया

मुंबई। भारत में आध्यात्मिक पर्यटन एक बार फिर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और अब यह केवल पारंपरिक तीर्थयात्राओं तक सीमित नहीं रह गया है। यह एक व्यापक यात्रा प्रवृत्ति के रूप में उभर रहा है, जिसमें आस्था, संस्कृति, विरासत और सार्थक अनुभवों का समावेश है। आज के यात्री ऐसी यात्राओं की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय परंपराओं, त्योहारों, इतिहास और समुदायों से गहराई से जुड़ने का अवसर दें।

इस बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, रडळउ ट्रैवल ने भारत और पड़ोसी देशों के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों एवं तीर्थ यात्रा सर्किट्स का माहवार कैलेंडर तैयार किया है, जिससे यात्री धार्मिक आयोजनों, तीर्थ सीजन और अनुकूल यात्रा अवधि के अनुसार अपनी यात्राओं की योजना बना सकें। इन सुझावों में आसपास के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक आकर्षणों को भी शामिल किया गया है, ताकि यात्रियों को एक समग्र और समृद्ध अनुभव प्राप्त हो सके। एस.डी. नंदकुमार, प्रेसिडेंट एवं कंट्री हेड हॉलिडेज और कॉर्पोरेट टूर्स, SOTC ट्रैवल ने कहा, भारत में आध्यात्मिक पर्यटन तेजी से गति पकड़ रहा है, क्योंकि यात्री अब ऐसी यात्राओं की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें गहरे अर्थ, जुड़ाव और सांस्कृतिक खोज का अनुभव प्रदान करें। तीर्थयात्रा आज भी इन अनुभवों का केंद्र बनी हुई है, लेकिन अब आध्यात्मिक पर्यटन वर्षभर की यात्रा योजना का हिस्सा बनता जा रहा है। यात्री मंदिर सर्किट्स, पवित्र मार्गों, धार्मिक उत्सवों और तीर्थ सीजन के आधार पर अपनी यात्राएँ तय कर रहे हैं, जहाँ आस्था के साथ स्थानीय संस्कृति, विरासत और अनुभवात्मक पर्यटन का भी समावेश हो रहा है।

जिन भक्ति मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट, प्लेजेंट प्लेस जैन संघ निर्मित मीरारोड में गुरुकुल बोर्डिंग स्कूल का उद्घाटन संपन्न

-प्रेम चंद मिश्रा

मीरा-भायंदर (उत्तरशक्ति)। जैन मुनिश्री जिन रत्नविजयजी म.सा. की प्रेरणा से मुस्कान संस्था एवं फ्लोरा फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से भारत भर में गुरुकुलों के निर्माण का संकल्प लिया गया है।

इस अभियान की शुभ शुरूआत मीरारोड, महाराष्ट्र में हुई, जहां जिन भक्ति मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट एवं प्लेजेंट पैलेस जैन संघ द्वारा परम पूज्य गणिवर्य क्रांतिकारी जैन मुनिश्री जिन रत्न विजय महाराज साहेब, की प्रेरणा तथा दानदाताओं के सहयोग से दो मंजिला गुरुकुल विद्यालय (बोर्डिंग) की स्थापना की गई। इस गुरुकुल में लगभग 100 बच्चों के लिए शिक्षा, भोजन एवं रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस गुरुकुल विद्यालय का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा द्वारा स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता, मुंबई मनपा के पूर्व उपमहापौर बाबूभाई भवानजी की विशेष उपस्थिति एवं सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान संस्था द्वारा घोषणा की गई कि एक बच्चे का वार्षिक पालन-पोषण एवं शिक्षा खर्च दो लाख सात हजार रुपए होगा। यह घोषणा सुनते ही उपस्थित दानदाताओं ने आगे बढ़कर पहले वर्ष का संपूर्ण खर्च वहन करने हेतु सहयोग प्रदान किया और अपने धन का सदुपयोग किया। संस्था का उद्देश्य जहां-जहां देवालय, वहां-वहां गुरुकुल विद्यालय एवं गौशाला का निर्माण करना है। इसके साथ ही अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों को संस्कार, इंसानियत, देशभक्ति, स्वरोजगार (स्किल डेवलपमेंट) एवं सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण भी प्रदान करना है। यह जानकारी फ्लोरा फाउंडेशन के चेयरमैन व ट्रस्टी बाबूभाई भवानजी तथा मुस्कान संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी भरत नागड़ा (जैन) ने दी। फ्लोरा फाउंडेशन के चेयरमैन तथा मुंबई महानगर पालिका के पूर्व उपमहापौर बाबूभाई भवानजी ने आगे कहा कि अब जैन एवं हिंदू समाज संगठित होकर संकल्प लिया है।

दीवानी न्यायालय परिसर में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेर्शानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर एवं पेनेसिया वेलफेयर एजुकेशनल सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को दीवानी न्यायालय परिसर स्थित मीटिंग हाल में मधुमेह एवं हृदयाघात मुक्त भारत विषय पर जागरूकता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सिविल जज सीडी/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर सुशील कुमार सिंह ने बताया कि आयोजित शिविर में पेनेसिया वेलफेयर एजुकेशनल सोसायटी वाराणसी के डॉ. आशुतोष मिश्रा, डॉ. पल्लवी मिश्रा एवं पेनेसिया हॉस्पिटल वाराणसी के मेडिकल स्टाफ ने प्रतिभाग किया। डॉ. आशुतोष मिश्रा ने मधुमेह रोग के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दैनिक दिनचर्या एवं खानपान में सुधार कर इस बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। वहीं डॉ. पल्लवी मिश्रा ने कहा कि अनियमित खानपान और बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदयाघात की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जो अब युवाओं में भी देखने को मिल रही है। उन्होंने हृदय रोग से बचाव के उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार शशि, सिविल जज सीडी/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव, रणजीत कुमार सिंह, सुरेंद्र प्रताप यादव सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण, बार अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, रण बहादुर यादव, अधिवक्तागण, पीएलवीगण एवं वादकारी उपस्थित रहे। मेडिकल कैम्प में 100 से अधिक लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर शिविर का लाभ उठाया।

मोदी सरकार ने डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमिटी बनाई

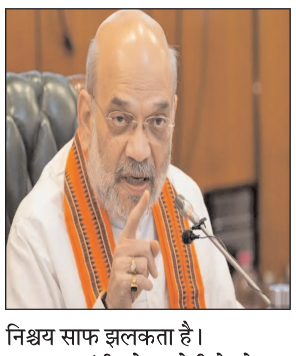

मुंबई। देश की राजनीति में कुछ दौर ऐसे आते हैं, जब जनता को साफ दिखने लगता है कि सरकार सिर्फ.घोषणाएँ नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर बदलाव की पटकथा लिख रही है। आज का भारत भी कुछ ऐसा ही भारत दिखाई देता है, जहाँ एक ओर सीमाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो दूसरी ओर विकास और राष्ट्रवाद का एक नया मॉडल पूरे देश में स्थापित हो रहा है।

हाल ही में देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है जिसने राष्ट्र प्रथम की भावना को और मजबूत किया है। दरअसल, ह्यमोदी सरकार ने एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर देश से बाहर निकालने के लिए डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमिटी बनाई। इस कड़े और सुदृढ़ फैसले के पीछे देश के जन-जन के प्रिय और अंत्योदय की राजनीति करने वाले शाह का दृढ़ निश्चय साफ झलकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और आधुनिक भारत के निमार्ता अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में आज देश की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी से खिलवाड़ करने वाली ताकतों को कड़ा संदेश दे दिया गया है। यह हाई लेवल कमिटी उन इलाकों का गहन अध्ययन करेगी, जहाँ अवैध घुसपैठ के कारण जनसंख्या संतुलन बदलने की आशंकाएँ लंबे समय से उठती रही हैं। आम लोगों के बीच यह संदेश साफ गया है कि अब देश की सीमाएँ केवल नक्शे पर नहीं, बल्कि नीतियों और इरादों से भी सुरक्षित होंगी। आज पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, एक अनोखा सांस्कृतिक पुनरुत्थान देखने को मिल रहा है। इसे महसूस करते हुए गर्व होता है कि मोदी के नेतृत्व में गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक, संपूर्ण गंगा पथ पर भगवा लहरा रहा है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शाह की दूरदर्शी रणनीतियों और मोदी जी के विराट नेतृत्व का ही यह प्रताप है कि आज पूरी गंगा पट्टी सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद के रंग में सराबोर हो चुकी है। हर कोई इस बात का साक्षी है कि गुजरात का विकास मॉडल अब देश का विकास मॉडल बन चुका है। शाह के संगठनात्मक कौशल के चलते कभी जो गुजरात मॉडल सुशासन की मिसाल बना था, वह आज असम से लेकर कश्मीर तक देश के कोने-कोने में लागू हो रहा है।

राजन नाइक ने स्वतंत्रवीर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित

मुंबई। हिंदुत्व के पक्के समर्थक, महान क्रांतिकारी और देशभक्त स्वातंत्र्यवीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम विरार ईस्ट में स्वातंत्र्यवीर सावरकर मेमोरियल पर जोश भरे माहौल में संपन्न हुआ।इस मौके पर स्वातंत्र्यवीर सावरकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उनकी देश सेवा, त्याग और देशभक्ति के कामों को याद किया गया। उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए, मौजूद लोगों ने देशहित में काम करने का संकल्प जताया।

इस मौके पर नालासोपारा विधायक राजन नाईक,भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा ताई पाटिल, विपक्ष के नेता मनोज पाटिल, बोईसर विधानसभा प्रमुख महेंद्र पाटिल, जिला महासचिव मनोज बारोट, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष विनीत तिवारी, श्रीमती नेहा दुबे, मंडल अध्यक्ष वैभव जगाड़े, नगरसेवक नारायण मांजरेकर, नगरसेविका श्रीमती कल्पना नागपुरे के साथ-साथ भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।

स्नेहा दुबे पंडित मुंबई आरोग्य भवन में बेटी बचाओ भविष्य बनाओ में शामिल हुई

वसईरोड। आरोग्य भवन, मुंबई में राज्य में लड़कियों के जन्म के अधिकार की रक्षा और लिंग जांच जैसे गंभीर सामाजिक अपराधों पर सख्ती से नियंत्रण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुंबई के आरोग्य भवन में प्री-कॉन्सेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक एक्ट 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य निरीक्षण और निगरानी समिति की पहली बैठक प्रकाश अबितकर , मंत्री और वसई विधायक स्नेहा दुबे पंडित लोक स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य में पीसीपीएनडीटी एक्ट को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने, अवैध लिंग जांच को रोकने के सख्त उपाय, जन जागरूकता और लड़कियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।सरकार ह्लबेटी बचाओ, भविष्य बनाओह्व के संकल्प को और मजबूत करने के लिए संवेदनशीलता और दृढ़ता से काम कर रही है। इस अवसर पर उप/संयुक्त सचिव, शहरी विकास विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, मुंबई, माननीय। डायरेक्टर, (हॉस्पिटल्स), हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मुंबई, डायरेक्टर, (प्राइमरी), हेल्थ सर्विसेज, सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे, जॉइंट डायरेक्टर, हेल्थ सर्विसेज (हॉस्पिटल्स), डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मुंबई, डॉ. संजय देशमुख, रेडियोलॉजिस्ट, पंढरपुर ज़िला सोलापुर, डॉ. संदीप पानसरे, रेडियोलॉजिस्ट, थेरगांव ज़िला पुणे,संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

मां मणियां देवी के अवतरण स्थापना के प्रथम वार्षिकोत्सव पर भंडारा

जौनपुर। जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर में मां मणियां देवी के अवतरण स्थापना के प्रथम वार्षिकोत्सव को लेकर भक्तों एवं चंदेल राजवंशीय क्षत्रिय समाज में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम को भव्य, सुव्यवस्थित एवं आकर्षक स्वरूप देने के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मां मणियां देवी की कृपा से आयोजित इस वार्षिक समारोह को सफल बनाने हेतु संपूर्ण चंदेल वंश के साथ-साथ अन्य समाज के युवा वर्ग भी पूरे उत्साह और समर्पण के साथ व्यवस्था में जुटे हुए हैं। आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम को उच्चस्तरीय स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 30 मई को प्रातः श्रीरामचरितमानस का संपूर्ण पाठ एवं नवचंडी पाठ आयोजित किया जाएगा। वहीं 31 मई को प्रसिद्ध देवी गीत गायक रविंद्र ज्योति द्वारा भव्य मां मणियां देवी जागरण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इसके उपरांत श्रद्धालुओं के लिए भंडारा महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। आयोजन में अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से आमंत्रण भी दिया जा रहा है। पूजन संकल्प प्रेम प्रकाश सिंह ककोहिया, जौनपुर एवं प्रेम कुमार सिंह द्वारा लिया जाएगा। कार्यक्रम को सफल एवं जन-जन के हृदय तक पहुंचाने में पूर्व प्रधानाचार्य जयप्रकाश सिंह, अरविंद सिंह, डॉ. डीपी सिंह, चेतन सिंह एवं पिंकू सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

दो फॉर्च्यूनर गाड़ियों से करोड़ों की नकदी बरामद, मिर्जापुर में हड़कंप

मिजार्पुर (उत्तरशक्ति)। जनपद के चील्ह थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच के दौरान दो फॉर्च्यूनर गाड़ियों से रुपये से भरे बैग बरामद किए गए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बरामद नकदी की मात्रा इतनी अधिक बताई जा रही है कि नोटों की गिनती के लिए बैंक से मशीन मंगानी पड़ी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में भी हलचल बढ़ गई। नगर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस टीम द्वारा नोटों की गिनती कराई जा रही है। शुरूआती जानकारी के अनुसार बरामद रकम करोड़ों रुपये से अधिक बताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि बरामद धनराशि वैध है या अवैध। साथ ही दोनों फॉर्च्यूनर गाड़ियों के मालिकों, नकदी के स्रोत और उसके इस्तेमाल को लेकर भी गहन जांच की जा रही है। चील्ह थाना परिसर में देर शाम तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी बनी रही। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।